समुदाय व संरक्षण

समुदाय आधारित जैवविविधता संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा

अंक १०, नं. २ सितंबर २०२१- मार्च २०२२

विषय सूचि

प्रस्तावना

१. समाचार और जानकारी

- लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण ओडिशा के स्वयं सहायता समूहों ने किस प्रकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की मदद की
- विकल्प वार्ताएँ – ऑनलाइन प्रस्तुतियों और वार्तालापों की शृंखला

२. दृष्टिकोण

कोविड –१९ के पहले वर्ष से मिले सबक से क्या हम कुछ सीख रहे हैं?

३. भारत से आशा की कहानियाँ

थीम: स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन: स्थानीय आदान–प्रदान की प्रणालियों को मज़बूत करना; संपर्क के डिजिटल माध्यम उपयोग करना

- स्थानीय उत्पादन और बिक्री की मज़बूती: केरल के श्रीलक्ष्मी महिला समूह का अनुभव
- कोविड–१९ की प्रतिक्रिया में महिला किसानों के लिए खाद्यान्न एवं कृषि क्षेत्र में तन्यकता बनाना
  थीम: किसान – उपभोक्ताओं के बीच सीधी कड़ियाँ
- थानामिर सेब: एकता की मज़बूती
- गुड़गाँव किसान बाज़ार
  थीम: ईकोपर्यटन संबंधित गतिविधियों के माध्यम से आजीविका के अवसर बढ़ाना
- बड्र्स ऑफ कश्मीर ने ईकोपर्यटन और आजीविका निर्माण के लिए रास्ता दिखाया
- स्प्रेड एन.ई. : स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका
  थीम: सूक्ष्म वनोपज तक पहुँच पर आधारित आजीविकाएँ और वन संसाधन; सामुदायिक वन प्रबंधन
- ग्राम सभाओं के नेतृत्व में प्रशासन
- बाहरी पलायन में गिरावट
  थीम: लॉकडाउन के समय का सदुपयोग
- सामुदायिक जुड़ाव चुनौती – युवाओं में नागरिक जागरूकता और नेतृत्व विकास
- महामारी में भी सीखना जारी: उत्तराखंड के युवा प्रकृति गाइड

४. अन्य देशों से तन्यकता की कहानियाँ

- कोविड–१९ की प्रतिक्रिया में एकजुटता और तन्यकता बढ़ाने के लिए पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करना
- जीवन के बीज, जल का उत्पादन
  विकल्पों पर प्रकाश डालने के विषय पर विशेष संस्करण

वैकल्पिक प्रयासोंपर विशेष अंक

प्रस्तावना

लियोनार्ड कोहेन, कनाडा के मशहूर कवि और गायक, ने नाउम्मीदी के समय में आशा रखने के बारे में लिखा था:

एक दरार है, हर चीज़ में एक दरार
उसी से किरणें अंदर आती है

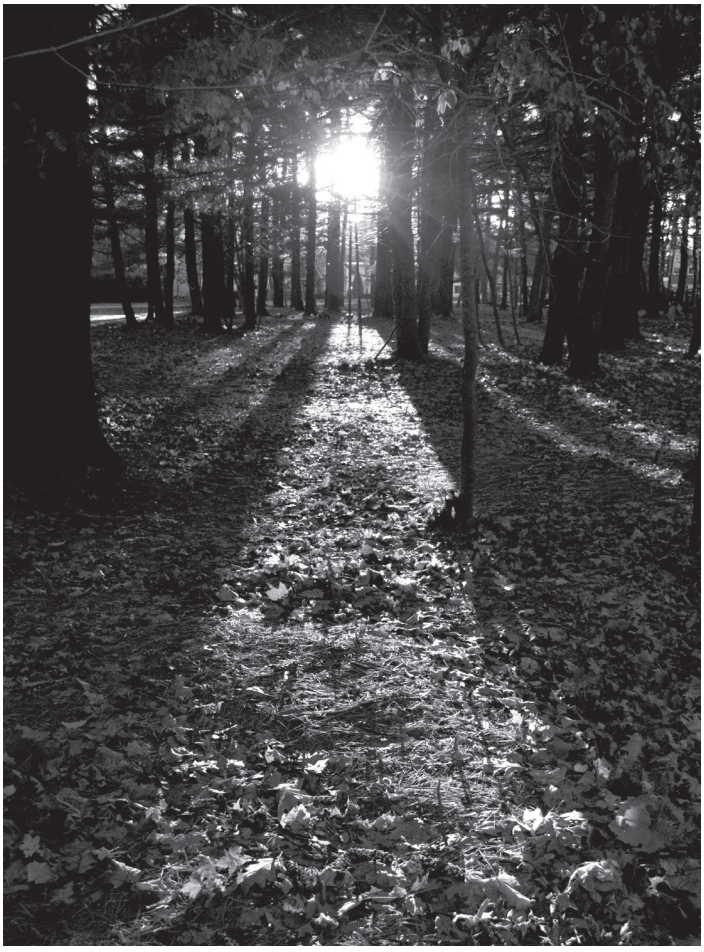

कोहेन का गाना, ऐन्थम, कुछ हद तक, जॉन होलोए (आयरलैंड के एक मार्क्सवादी समाजवादी) के प्रणालियों में दरार बनाने के दृष्टिकोण से मेल खाता है, जहाँ प्रणाली का मतलब है पूंजीवादी प्रणाली और सत्ता के ढांचे। होलोए ने स्थानीय विकल्पों को दरार के रूप में परिभाषित किया, चाहें वे कितने ही बड़े या छोटे हों। उदाहरणों के रूप में, किसानों की सहकारी समितियाँ स्थापित करने, बड़े उद्योगों में हड़ताल करने, या फिर शिक्षा की बढ़ती कीमतों के खिलाफ छात्रों के विरोध की बात की थी (दास २०१७)।

कोविड–१९ महामारी के पिछले दो वर्ष बेहद मुश्किल रहे हैं जहाँ पूरे विश्व के लोगों में नाउम्मीदी और निराशा भर गई। और इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग थे समाज के हाशिये के लोग: असंगठित वर्ग, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मज़दूर, शिल्पकार, आदिवासी लोग, विकलांगता के साथ जी रहे लोग, शहरी इलाकों में पलायनरत मज़दूर और मछुआरे।

लेकिन इस सब उदासी के बीच, उम्मीद की कई कहानियाँ भी उभर कर आईं, स्थानीय, क्रांतिकारी विकल्पों की कहानियाँ जिन्होंने स्थानीय समुदायों को आकस्मिक लॉकडाउन, आजीविकाएँ और बाज़ारोंतक पहुँच खो देने, और खराब स्वास्थ्य प्रणाली की स्थितियों में तन्यकता बनाने में मदद की। बहुत–से विकल्प हैं और वे स्थानीय प्रशासन, वन संसाधनों तक सामुदायिक पहुँच और अधिकारों, स्थानीय बाज़ारों के साथ सीधे जुड़ाव, उत्पादक–उपभोक्ता प्रत्यक्ष जुड़ाव, पारिस्थितिकीय कृषि प्रणालियों, महिला समूहों के सशक्तिकरण, घरेलू सब्ज़ी उत्पादन और सामुदायिक स्वास्थ्य सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं।

इस संस्करण में, हम भारत से इन विकल्पों की छोटी कहानियाँ साझा कर रहे हैं जिन्हें इससे पहले, विकल्प संगम प्रक्रिया द्वारा प्रकाशित एक शृंखला में छापा गया था (जिनका शीर्षक है ''साधारण लोगों के असाधारण काम'') (<https://vikalpsangam.org/article/extraordinary-work-of-ordinary-people-in-multi-language-translation/>), और दो अन्य देशों की कहानियाँ जिन्हें ग्लोबल टैपिस्ट्री ऑफ ऑल्टरनेटिव्स (<https://globaltapestryofalternatives.org/reports:pandemic:index>) द्वारा प्रकाशित ''वीविंग सालिडैरीटी एण्ड होप: बेयोंड पैन्डेमिक्स एण्ड लॉकडाउन्स के पहले संस्करण में छापा गया था।''

हम उम्मीद करते हैं यह कहानियाँ न्यायपूर्ण और पारिस्थितिकीय रूप से तन्यकतापूर्ण वैकल्पिक दुनिया की आशा और संभावनाओं को जीवित रखेंगी। तब तक, हमें याद रखना होगा: कि इसी से किरणें अंदर आती हैं!

सुजाता पद्मनाभन

दास, पल्लव। २०१७. द पॉवर इक्वेशन एण्ड इंडियाज़ फ्यूचर। आशीष कोठारी और के.जे. जॉय (संपादित), ऑल्टरनेटिव फ्यूचर्स: इंडिया अनशैकल्ड, ऑथर्सअफ्रन्ट, नई दिल्ली, पृष्ठ १०३–११९

१. समाचार और जानकारी

लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण ओडिशा के स्वयं सहायता समूहों ने किस प्रकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की मदद की

प्रदीप बैसाख

मधु बाबू स्वयं सहायता समूह की प्रतिमा हरिजन (दाहिने हाथ पर) अपने ऑटोरिक्शा के साथ। चित्र: संध्या बैसनब

ओडिशा के मलकनगिरि ज़िले के कालीमेला खंड में एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। फलों और सब्ज़ियों से भरे खेतों में कुछ किसानों ने अपने मवेशियों को चरने के लिए खुला छोड़ दिया। सच तो यह है कि उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। अपने खेतों की उपज बेचने की कोई उम्मीद न होने के कारण, किसानों ने तय किया कि वे उसे अपने मवेशियों को खिला देंगे। साधारण तौर पर, स्थानीय व्यापारी इस उत्पादन को खरीद लेते, और फिर आंध्र प्रदेश के रायपुर और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भेज देते। या फिर अपने ही राज्य की राजधानी भुबनेश्वर में, जो कि कालीमेला से ६५० कि. मी. दूर है। लेकिन वहाँ लॉकडाउन लगा था – मांग गिर रही थी और यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। सब्ज़ियाँ बिकनी बंद हो चुकी थीं।

फिर खंड अधिकारियों को एक विकल्प सूझा: कि स्वयं सहायता समूहों से कहा जाए कि वे खेतों के उत्पादन को खरीद लें और स्थानीय उपभोक्ताओं को बेच दें। यह विचार काम आया। ज़्यादातर बाज़ार बंद थे और आवाजाही पर रोक के कारण, लोगों को सब्ज़ियाँ व अन्य आवश्यकता की चीज़ें खरीदने में मुश्किल हो रही थी।

एक स्वयं सहायता समूह से दूसरे स्वयं सहायता समूह तक

पिछले कुछ वर्षों में ओडिशा में कई स्वयं सहायता समूह बने हैं, जिन्हें सरकार और गैर–सरकारी संस्थाओं से सहयोग मिल रहा है, और इसके पीछे विचार है कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करके उनके परिवारों के लिए कुछ आमदनी सुनिश्चित की जाए। इसलिए, अप्रैल के पहले सप्ताह में, प्रशासन ने इनमें से कुछ स्वयं सहायता समूहों को कालीमेला में इस योजना में जुड़ने के लिए आग्रह किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया और जल्द ही श्रम के बंटवारे की एक प्रणाली भी तैयार कर ली। पहले, ओडिशा लाइव्लीहुड मिशन के सदस्य किसानों और उनके उत्पाद की पहचान करेंगे, फिर कुछ स्वयं सहायता समूह फल और सब्ज़ियाँ खरीद कर दूसरे स्वयं सहायता समूह को बेचेंगे। फिर दूसरा स्वयं सहायता समूह गाँव वालों को घर–घर जाकर उन्हें बेचेगा।

यह एक स्वयं सहायता समूह से दूसरे स्वयं सहायता समूह तक का मॉडल बन गया, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में बिज़नेस से बिज़नेस मॉडल प्रचलित हैं। ''इस मॉडल ने काफ़ी अच्छा काम किया,'' रॉसलिन दास, ओडिशा लाइव्लीहुड मिशन। उन्होंने इसके पीछे का तर्क समझाते हुए कहा: ''कुछ स्वयं सहायता समूह किसानों से फल और सब्ज़ियाँ खरीदने में सक्षम थे, लेकिन उनको यातायात करने के लिए हमने ऐसे स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया, जिनके सदस्यों के पास या तो ऑटोरिक्शा थे या वो ऑटोरिक्शा ला सकते थे। इस तरह से श्रम के बंटवारे से काम आसान हो गया।''

सहज परिचालन

उन्होंने जो सब्ज़ियाँ बेचीं, उनमें शामिल थीं बैंगन, टमाटर, करेले, खीरे, भिंडी, मिर्च, मीठा भुट्टा और कद्दू, और इसके अतिरिक्त केले और तरबूज जैसे फल भी। कुछ १७ स्वयं सहायता समूह खरीदने में शामिल थे, और ६९ समूहों ने घर–घर जाकर बेचने का काम संभाला।

उत्पाद को अन्य गांववालों को बेचने के अलावा, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बुजुर्ग और निःसहाय लोगों को खाना देने के लिए चलाई जा रही सरकारी निःशुल्क रसोइयों में भी उत्पाद पहुंचाया।

यह सब्ज़ियाँ पंचायत–स्तरीय क्वॉरन्टीन केंद्रों में भी पहुंचाई गईं। जहां खंड अधिकारियों ने विभिन्न एजेंसियों के साथ इस प्रक्रिया को सहजता से चलाने के लिए समन्वय किया, सरकार ने ज़रूरतमन्द स्वयं सहायता समूहों को रु. ५०,००० से रु.१,००,००० तक के कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाए। महिलाओं तक यह राशि मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से पहुंचाई गई।

यह योजना जल्द ही इतनी प्रचलित हो गई कि कॉल–एण्ड–डिलिवर सेवा के मोबाईल नंबर न सिर्फ ऑटोरिक्शाओं के पीछे पेंट होने लगे, बल्कि महिलाओं ने भी मछली और दूध लेकर डिलिवर करना शुरू कर दिया, जिसके लिए इन ऑटोरिक्शाओं में बैटरी से चलने वाले फ्रिज लगाए गए।

सार्वजनिक हित

चम्पा किसानी दसवीं कक्षा तक पढ़ी है। वो पोटाखल गाँव के बिस्वा माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हुई है। ''सब्ज़ियाँ सड़ रही थीं। हमने उन्हें किसानों से खरीदा और अन्य स्वयं सहायता समूहों को छोटे मुनाफे पर बेचा। हम प्रतिदिन रु.५००–७०० कमा लेते थे,'' किसानी ने बताया। इस पैसे को अब मछली पालन तथा रसोई खेती में निवेश किया गया है।

प्रतिमा हरिजन, ३८, मधु बाबू स्वयं सहायता समूह की एक आदिवासी महिला, मुश्किल से अपने नाम का हस्ताक्षर कर पाती है लेकिन कहती है कि उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर ''ऑटोरिक्शा चलाए और लोगों को उनके घरों तक सब्ज़ियाँ पहुंचायीं।'' रु.५००–१००० प्रतिदिन की छोटी कमाई से उन्हें लॉकडाउन के दौरान अपने घर का खर्च चलाने में मदद मिली। सबको फायदा मिला। किसान अपने उत्पाद बेच पाए, गाँव की महिलाओं ने कुछ मुनाफ़ा कमा लिया, और उपभोक्ताओं को उनके घर पर सब्ज़ियाँ मिल गईं।

जल्द ही मलकनगिरि ज़िले के सभी खंडों में यह योजना चलने लगी। इससे जलवायु–संबंधित लाभ भी मिले – उत्पाद को अब कई लिटर पेट्रोल/डीज़ल फूँक कर दूर तक नहीं ले जाना पड़ रहा था। ऐसे मुश्किल समय में सामुदायिक स्तर के समाधान से एक नई प्रणाली ने जन्म लिया।

अब, जब लॉकडाउन खत्म हो गया है और स्थिति वापस साधारण हो रही है, कालीमेला में अब भी कुछ सात–आठ ऑटोरिक्शा चल रहे हैं, जो कि इस प्रणाली की सततता को दर्शाते हैं। संभव है कि मांग और आपूर्ति काफ़ी लंबे समय तक चलेगी।

द हिन्दू (ऑनलाइन संस्करण) में ८ अगस्त, २०२० को प्रकाशित।
<https://www.thehindu.com/society/how-self-help-groups-in-rural-odisha-helped-both-farmers-and-consumers-during-lockdown/article32294535.ece>

विकल्प वार्ताएँ – ऑनलाइन प्रस्तुतियों और वार्तालापों की शृंखला

कोविड–१९ के कारण हुए लॉकडाउन और लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर मिलने में आने वाली समस्याओं के मद्देनज़र, और साथ ही स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकट में समुदायों की प्रतिक्रियाओं को आवाज़ देने के उद्देश्य से, अप्रैल २०२० में विकल्प संगम प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन प्रस्तुतियों और विमर्श की एक शृंखला शुरू की गई जिसका शीर्षक था विकल्प वार्ता।

वर्ष २०२० में २१ वार्ताएँ आयोजित की गईं; दूसरी शृंखला २०२१ में शुरू की गई। इन वार्ताओं की रिकॉर्डिंग यहाँ पर उपलब्ध हैं:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVGJfYVd8JMXoo4JE-0JNBoQk2fzxL9vK

और

https://www.youtube.com/watch?v=3vRpoOVfF9o&list=PLVGJfYVd8JMWeHoK6UxG-irmG3gTUUqAN

✧✧

२. दृष्टिकोण

कोविड -१९ के पहले वर्ष से मिले सबक से क्या हम कुछ सीख रहे हैं?

आशीष कोठारी

कोविड की एक और लहर, लॉकडाउन का एक और सिलसिला, और पालयनरत मज़दूरों के लिए एक बार फिर अपने घर जाने के लंबे सफ़र की तैयारी। साल भर कोविड-१९ से एक चीज़ जो हमने सीखी वो यह है कि हमने कोई सबक नहीं सीखा, कम-से-कम जो ज़रूरी सबक थे, वो तो नहीं।

वर्ष २०२० ने हमारी आर्थिक प्रणाली की अथाह खामियों को उजागर कर दिया जो कि लाखों लोगों को असुरक्षित नौकरियों की ओर धकेलती है, जिन्हें वे एक रात भर में खो सकते हैं, और उनके पास कोई विकल्प नहीं होता या कोई सुरक्षा का जाल नहीं होता। भारत के असंगठित कार्यक्षेत्र के ९०% कामगारों में से अधिकतर की यही सच्चाई है। विकास के पिछले कुछ दशकों में, आर्थिक नीतियों ने राजकीय-प्रभुत्व वाले या पूंजीवादी औद्योगिक वर्ग के लिए सस्ते श्रम का एक विशाल पूल तैयार किया है, जो कि पहले से विशाल संख्या में मौजूद और जाति, वर्ग तथा जेन्डर भेदभाव में फंसे भूमिहीन कृषि मज़दूरों की गिनती में जुड़ गया। १९९१ से, लगभग १.५ करोड़ किसान खेती करना छोड़ चुके हैं, और ज़्यादातर इसलिए क्योंकि आर्थिक प्रणाली ने कृषि (जिसमें चरवाहा, मछलीपालन और वानिकी से जुड़े व्यवसाय शामिल हैं) को लाभदायक ही नहीं छोड़ा है। और लगभग ६ करोड़ लोग बांधों, खनन, एक्स्प्रेसवे, बंदरगाहों, स्मारक प्रतिमाओं, उद्योगों के कारण विस्थापित हुए हैं जिनका या तो कोई पुनर्वास नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो बहुत बुरी तरह से। और इस सबके बीच, किसी भी प्रकार के काम के लिए मजबूर लोगों, और प्रकृति का शोषण करके कुछ अल्पसंख्यक लोग हर सेकंड में और ज़्यादा अमीर बनते चले जा रहे हैं। भारत के सबसे अमीर ५% लोगों की आमदनी बाकी ९५% भारतीयों की आमदनी के बराबर हो गई है।

जैसा कि असीम श्रीवास्तव और मैंने चरनिंग द अर्थ में दर्शाया है, १९९१ में वैश्विक वित्तीय ताकतों के सामने भारत सरकार के समर्पण के कारण करोड़ों लोगों की संवेदनशीलता और अधिक बढ़ गई और हमारे पर्यावरण को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंची। निश्चित तौर पर, भारत के सभी असंगठित कार्यक्षेत्र के कामगार असुरक्षित हैं यह ज़रूरी नहीं है; किसान, मछुआरे, चरवाहे, वन-निवासी, शिल्पकार, मनोरंजन करने वाले, तुलनात्मक रूप से सुरक्षित हैं अगर उनके संसाधन (ज़मीन, प्रकृति, उपकरण, ज्ञान, उपभोक्ता) बरकरार हैं, या उन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना की सुरक्षा प्राप्त है। लेकिन फिर यह लोग सस्ती मज़दूरी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें या उनकी अजीविकाओं को विकास के नाम पर विस्थापित करना होगा। पिछले वर्ष सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के कारण कृषि में कॉर्पोरेट का नियंत्रण और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे और अधिक सस्ते और शोषण करने लायक मज़दूर उपलब्ध हो जाएंगे। किसान इस बात को जानते हैं, जो उनके लंबे आंदोलन की तीव्रता और संकल्प को स्पष्ट करती है।

यह सच है कि गांवों में केवल कृषि से सबको रोज़गार नहीं मिल सकता। और यह भी कि युवा पारंपरिक व्यवसायों में रहना नहीं चाहते खासकर यदि वे व्यवसाय जाति और जेन्डर भेदभाव से जुड़े हुए हों। लेकिन ऐसी वास्तविकताएँ जड़ से इन मुद्दों का समाधान करने में हमारी विफलता के कारण पैदा होती हैं। कुछ भी हो, १९९१ से औपचारिक कार्यक्षेत्र में ज़्यादातर बेरोज़गार विकास हुआ है, जिसका मतलब है कि गाँव छोड़कर आने वाले लोग कोई और अनौपचारिक काम करने के लिए विवश हो जाते हैं, जो कि ज़्यादातर असुरक्षित होता है।

लेकिन इस धुरी के विकल्प भी हैं, और वे स्पष्ट सीख भी प्रदान करते हैं। २०२० के मध्य से, हमने दर्जनों ऐसे उदाहरण इकट्ठे किए हैं जिन्हें हम साधारण लोगों के असाधारण काम कहते हैं – बेयोंड पैन्डेमिक्स एण्ड लॉकडाउन्स (https://vikalpsangam.org/?s=Extraordinary+Work)। कोविड-१९ के बीच, कई समुदायों के पास खाने के लिए पर्याप्त उपलब्ध था, अपनी आजीविका चलाने के लिए गरिमापूर्ण साधन थे, सबसे कमज़ोर वर्ग को मदद करने के लिए सामुदायिक एकजुटता प्रणालियाँ थीं, सामूहिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ जिन्होंने सुनिश्चित किया कि वायरस बड़े पैमाने पर न फैले, और बच्चों के लिए सीखने के वैकल्पिक तरीके जिनमें उन्हें मज़ा भी आए।

तेलंगाना और नागालैंड में, क्रमशः, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी की दलित महिलाओं और नॉर्थ-ईस्ट नेटवर्क की आदिवासी महिलाओं ने २०२० के वर्ष में कई दर्जनों गांवों में संपूर्ण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। तमिल नाडु की सिट्टीलिंगी पंचायत और कच्छ की कुनरिया पंचायत की सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालियों ने कोविड को ज़ोर पकड़ने का मौका ही नहीं दिया। असम में, फार्म २ फूड ने कई हज़ार छात्रों के साथ मिलकर स्कूलों और समुदायों में खाद्य पदार्थ पैदा करना जारी रखा। कोलकाता में, युवा समूह प्रांतकथा ने ३२ विधवा महिलाओं के लिए स्थानीय सुरक्षा जाल बनाया जिन्हें इससे पहले भीख माँगनी पड़ती थी। पश्चिमी हिमालय में तितली ट्रस्ट, बर्ड्स ऑफ कश्मीर, सीडर, और स्नो लेपर्ड कन्सर्वन्सी इंडिया ट्रस्ट ने स्थानीय समुदायों के साथ स्थानीय गाइड गतिविधियां जारी रखीं, जिससे कि पर्यटन के वापिस शुरू होने पर स्थानीय स्तर पर कुशलताएँ तैयार रहें। बीजोत्सव

नागपूर, द गुड़गाँव ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट, तमिल नाडु में नवदर्शनम द्वारा संचालित गांवों के स्वयं सहायता समूह, मध्य प्रदेश में समाज प्रगति सहयोग, और उत्तराखंड में महिला उमंग समिति सुनिश्चित कर पाए कि खेतों का उत्पाद (ज़्यादातर स्थानीय) उपभोक्ताओं तक पहुँच सके, जिससे हज़ारों किसान आर्थिक रूप से तबाह होने से बच गए।

विकल्पों की यह व अन्य हज़ारों कहानियाँ (ृ.ींळ्झरश्रींरिपसरा.ीस), बेहद महत्वपूर्ण सीख देती हैं। सबसे बड़ी सीख है कि दूर–दराज़ के बाज़ारोंऔर नौकरियों के मुकाबले, मूलभूत ज़रूरतों के लिए स्थानीय आत्मनिर्भरता, और स्थानीय स्तर पर उत्पाद तथा सेवाओं का आदान–प्रदान, लोगों की आजीविकाएँ सुरक्षित करने में ज़्यादा प्रभावकारी है। उत्पादन के अधिकांश भाग को बड़े उद्योगों को सौंप देने के बजाए, घर की लगभग सभी ज़रूरतों – साबुन, चप्पल/जूते, फर्निचर, बर्तन, कपड़े, ऊर्जा, यहाँ तक कि मकान, खाद्य पदार्थ, और पेय – सभी विकेन्द्रीकृत तरीके से हज़ारों समुदायों द्वारा तैयार किया जा सकता है। केवल कृषि–आधारित आजीविकाओं की कमी को शिल्प, लघु–उत्पादन, और अपने और आसपास के लोगों के लिए ज़रूरी सेवाओं के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। जैसा कि कच्छ में कुनरिया पंचायत के सरपंच सुरेश छंगा ने मुझे बताया, ङ्गङ्गअगर हम अपने घर की ज़रूरतों की अधिकांश चीज़ें खुद उत्पादन कर सकें तो हम न केवल बाहर की कंपनियों से इन्हें खरीदने पर हर महीने खर्च होने वाले ४० लाख रुपए बच सकते हैं, बल्कि हम सम्पूर्ण स्थानीय आजीविका सुरक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं।ङ्गङ्ग उत्तराखंड के महिला समूह माटी ने दर्शा दिया कि किस प्रकार समुदाय के नेतृत्व में ईको–पर्यटन के साथ–साथ खेती और शिल्प/कलाओं को जारी रखना ज़रूरी है जिससे कि एक बफर उपलब्ध रहे, अगर इनमें से कोई भी एक विफल हो जाए तो।

दुर्भाग्यवश, सरकार के हाल के घोषित पैकेज, जिन्हें आत्मनिर्भर का लेबल दिया गया है, असल में दूर–दराज़ के बाज़ारों और कंपनियों का लोगों के जीवन पर नियंत्रण बढ़ा रहे हैं, और पारिस्थितिकीय विनाश को भी (उदाहरण के लिए, केन्द्रीय भारत के कोयला खनन क्षेत्रों में जहां समुदाय अभी भी ज़मीन और जंगलों के आधार पर काफ़ी आत्मनिर्भर हैं)। जहां कुछ सरकारी कार्यक्रमों ने सबक सीख लिए हैं, जैसे कि केरल के कुडुम्बश्री कार्यक्रम में जो कि कई लाख महिलाओं को गरिमापूर्ण आजीविकाएँ प्रदान करता है, हमने देखा कि कोविड का सामना करने में वो कहीं ज़्यादा कामयाब रहे। ग्रामीण पुनर्जनन के ऐसे कई उदाहरण बाहर पलायन करने में महत्वपूर्ण गिरावट भी दर्शाते हैं, और कई जगहों पर तो शहरों से गांवों में लोगों की वापसी भी हुई है।

स्थानीय आत्मनिर्भरता को उत्पादन पर कामगारों के नियंत्रण, लोकतंत्र के और प्रत्यक्ष स्वरूप (स्वराज), और जातिवाद तथा जेन्डर भेदभाव खत्म करने के संघर्षों के साथ मिलकर काम करना होगा। एक बार फिर, इसके भी कई उदाहरण हैं। केन्द्रीय भारत में, समुदायों ने सफलतापूर्वक अपने आसपास के जंगलों पर सामुदायिक कानूनी नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, और आदिवासी स्वशासन के लिए लोगों को एकजुट भी किया, और वे कोविड लॉकडाउन का उन लोगों से बेहतर सामना कर पाए जिनके पास जंगलों पर अपना नियंत्रण नहीं था। स्पीति में, जैसे ही कोविड की पहली लहर आई, तो स्थानीय समुदायों ने पूरी स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्यान्न तथा आजीविकाओं में और ज़्यादा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षात्मक उपायों और सतत विकास के लिए एक कमिटी स्थापित कर दी। डी.डी.एस. की दलित महिला किसानों ने दिखा दिया कि जेन्डर और जाति भेदभाव से कैसे संघर्ष किया जाता है।

लेकिन सरकारें इस प्रकार के राजनैतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति सबसे ज़्यादा हिचकिचाती हैं। इससे उनकी सत्ता को खतरा पहुंचता है, और साथ ही उनकी मर्ज़ी से कारपोरेशनों को ज़मीनें और संसाधन बांटने की क्षमता को भी। ७३ वें और ७४ वें दोनों संवैधानिक संशोधन, जिनके द्वारा ग्राम सभाओं और नगर सभाओं का सशक्तिकरण होना था, या वनाधिकार अधिनियम जैसे कानूनों को बेमन से लागू किया जा रहा है। वर्तमान सरकार इन कानूनों और मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को कमज़ोर करने की कोशिश भी कर रही है, जो लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों के लिए जीवन रक्षक रहे हैं।

जो आर्थिक व्यवस्था व्यापक स्तर पर लोगों को संवेदनशील बनाती है, उससे सामाजिक विग्रह बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक, वर्ग और जाति आधारित हिंसा पनपने के लिए अनुकूल माहौल बन जाता है। अंत में यह हम सब को अपनी चपेट में ले लेगा, और केवल बेहद अमीर लोग इससे बच कर विश्व के किसी सुरक्षित हिस्से में चले जाएंगे।

कई लाखों लोगों को शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों की असुरक्षित, असम्मानजनक नौकरियों में वापस न जाना पड़ता, अगर उन्हें अपने ही गाँव या कस्बों में आर्थिक सुरक्षा मिल पाती। इस सब के लिए वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हैं, और कोविड–१९ संकट में उन्हें बखूबी काम भी किया। लेकिन क्या हम इनसे कुछ सीख रहे हैं?

स्त्रोत: https://indianexpress.com/article/opinion/columns/cornavirus-pandemic-india-informal-sector-economy-7285193/

✦✦

३. भारत से आशा की कहानियाँ

थीम: स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन: स्थानीय आदान–प्रदान की प्रणालियों को मज़बूत करना; संपर्क के डिजिटल माध्यम उपयोग करना

स्थानीय उत्पादन और बिक्री की मज़बूती: केरल के श्रीलक्ष्मी महिला समूह का अनुभव (लेखक: ऊषा एस. और अरुण आर.एस.)

थनल, १९८६ में स्थापित एक स्वैछिक अनुसंधान और कार्य समूह, जैवविविधता तथा पर्यावरणीय शिक्षा पर अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं पैरवी का काम करता आया है। पिछले दो दशकों में उनका प्रमुख कार्य जैविक खेती/ कृषि पारिस्थितिकी तथा खाद्य संप्रभुता, शून्य अपशिष्ट, केमिकल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर रहा है। थनल तृणमूल स्तर पर किसानों, सामुदायिक संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थाओं, पंचायतों, छात्रों आदि के साथ उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण पर काम करता है। थनल एक ऐसी संस्था है जिसने कई वर्ष पहले २००३ में जैविक खेती के जैविक उत्पादों को बेचने के काम की शुरुआत की और इसके माध्यम से उन्होंने किसानों और उपभोक्ताओं को एक सांझे मंच पर साथ लाया।

केरल के मशहूर पर्यटन स्थल कोवलम के नज़दीक, एक तटीय गाँव है वेलर। यह एक छोटी, पर्वतीय और सुंदर जगह है जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और प्रति परिवार ज़मीन का स्वामित्व काफ़ी छोटा। कई दशकों से यहाँ खेती प्रमुख आजीविका नहीं रही है। लेकिन प्रशासन के सक्रीय विकेन्द्रीकरण, महिला स्वयं सहायता समूहों की स्थापना, खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर जागरूकता, गांधी स्मारक निधि, थनल और वेंगनूर ग्राम पंचायत जैसी संस्थाओं द्वारा जैविक खेती पर प्रशिक्षणों के कारण यहाँ के लोगों की सोच में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस क्षेत्र के कई छोटे ज़मीन धारकों ने सब्ज़ियों, केले, पपीते और जिमीकंद की खेती करनी शुरू की। थनल से प्रशिक्षण प्राप्त लगभग ७० किसान, ज़्यादातर महिलाओं ने अपने खुद के प्रयोग तथा बाज़ार में बेचने के लिए जैविक सब्ज़ियों की खेती करनी शुरू की। शुरुआत में वे लोग व्यतिगत स्तर पर खेती कर रहे थे, जहां वे परिवार के अंदर ही श्रम करते थे लेकिन बाद में उनमें से कुछ लोगों ने छोटे–छोटे समूह बनाने शुरू कर दिए।

श्रीलक्ष्मी संगठन, जिसकी स्थापना २०१८ में १५ महिला किसानों के साथ हुई, ३.५ एकड़ ज़मीन पर जैविक सब्ज़ियाँ पैदा करने और बेचने का काम काम करता है। बीज और जैविक उत्पादन के संदर्भ में अब वे लगभग आत्म–निर्भर हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्हें कई समस्याएं आईं, जहां इन्हें बेचना उनके लिए मुश्किल हो गया। परिवारों की आमदनी खत्म हो गई क्योंकि वे बाहर काम करने नहीं जा पा रहे थे। इस क्षेत्र के ज़्यादातर लोग कोवलम पर्यटन स्थल में और उसके आसपास दिहाड़ी मज़दूरी या होटलों, दुकानों और ऐसी जगहों पर काम करते हैं।

लॉकडाउन के दौरान कोई यातायात उपलब्ध न होने के कारण, महिला किसान बाज़ार जा कर अपनी सब्ज़ियाँ नहीं बेच पा रही थीं। बाद में, श्रीलक्ष्मी समूह के कुछ सक्रीय सदस्यों को पता चला कि उनके पड़ोसियों को सब्ज़ियों की ज़रूरत है और उन्होंने फोन तथा अपने वार्ड सदस्यों की मदद से उनसे संपर्क बनाया। उन्होंने २५ परिवारों के ९० लोगों को विभिन्न सब्ज़ियाँ बेचने से शुरुआत की। उत्पादन बढ़ने लगा, जिसमें अच्छी धूप और बीच–बीच में बारिश ने काफ़ी सहायता की। इसके अतिरिक्त, लोगों के पास अब अपने खेतों पर ध्यान देने का समय भी था।

लॉकडाउन के दौरान, ऑर्गेनिक बाज़ार (त्रिवेंद्रम में थनल द्वारा स्थापित जैविक सामाजिक उद्योग – www.organic-bazaar.in http://www.organic-bazaar.in>) के स्टाफ ने सभी जैविक किसानों से फोन पर उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बात की। उन्होंने आगे बढ़कर उनके खेतों से सब्ज़ियाँ उठाने की पहल की और यह महिलाओं के समूह के लिए बहुत मददगार रहा। इससे कई स्थानीय छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने

चंद्रिका अम्मा अपने रसोई खेत में

श्रीलक्ष्मी महिला समूह से बीज लिए तथा सब्ज़ियाँ पैदा करनी शुरू कर दीं। यह महिलाएं संदर्भ टीम के रूप में काम करने लगीं, और नए सदस्यों को जैविक सब्जी उत्पादन में मदद करने लगीं।

महामारी के परिणामस्वरूप खाद्य उत्पादन पर चर्चाएं बढ़ीं और सरकार ने राज्य में सब्ज़ियों, कंद और फलों के उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय लिया। कृषि विभाग और कुडुम्बश्री मिशन ने बीज भेजना शुरू कर दिया। श्रीलक्ष्मी समूह के सदस्यों को भी कुडुम्बश्री मिशन से कुछ मदद मिली।

कोविड–१९ की प्रतिक्रिया में महिला किसानों के लिए खाद्यान्न एवं कृषि क्षेत्र में तन्यकता बनाना (लेखक: डब्ल्यू.जी.डब्ल्यू.एल.ओ.)

द वर्किंग ग्रुप फॉर विमेन लैंड ओनर्शिप (डब्ल्यू.जी.डब्ल्यू.एल.ओ.), गैर–सरकारी संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों का एक गैर–पंजीकृत लेकिन औपचारिक नेटवर्क, वर्ष २००२ से गुजरात में महिलाओं के भूमि अधिकारों के मुद्दे पर काम कर रहा है। पिछले १८ वर्षों में, इस नेटवर्क ने महिलाओं के भूमि अधिकारों को बढ़ावा देने; किसान के रूप में महिलाओं की पहचान स्थापित करने; और उत्पादनशील संसाधनों तथा अधिकारों तक पहुँच स्थापित करने के लिए काम किया है। डब्ल्यू.जी.डब्ल्यू.एल.ओ. ने विभिन्न रणनीतियों और प्रारूपों को बढ़ावा दिया है जैसे कि समुदाय आधारित अर्धन्यायिक कार्यकर्ताओं, और स्व–भूमि केंद्र के नाम से खंड–स्तरीय संसाधन केंद्र, जहां से प्राप्त होने वाली सीखें अन्य समान विचारधारा वाले नागरिक समाज नेटवर्कों तथा सरकार के साथ साझा की जाती हैं। स्व–भूमि केंद्र और अर्धन्यायिक कार्यकर्ता तथा महिला किसान सखियाँ केन्द्रीय, उत्तर–पूर्वी और दक्षिणी गुजरात के ११ ज़िलों, १५ खंडों के २२५ गांवों में आदिवासी, सामंतवादी, चरवाहा, व अन्य हाशिये के कृषक समुदायों की महिला किसानों के साथ काम करती हैं।

जब डब्ल्यू.जी.डब्ल्यू.एल.ओ. ने अपनी सदस्य महिला किसानों से लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद हुई समस्याओं के बारे में पूछा, तो उन्हें पता चला कि लगभग ९०% महिला किसानों को रबी की फ़सल की बिक्री में नुकसान हुआ। दक्षिण गुजरात के तापी ज़िले में सब्ज़ी पैदा करने वाले किसान अपनी फ़सलों को नष्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ अफ़वाह फैली थी कि सब्ज़ियों के कारण वायरस फैल रहा है! इन्हीं महिला किसानों को खरीफ़ के लिए बीज उधार लेने के लिए और ऋण लेना पड़ा; और इसके अतिरिक्त राशन, घरेलू चीज़ें आदि खरीदने के लिए भी। सुरेन्द्रनगर में पातड़ी की वसंतीबेन लवजीभाई ने अन्य महिला किसानों की समस्याओं को दोहराते हुए बताया कि उन्हें बीज के लिए रखे हुए अनाज को भी खाने के लिए निकाल लेना पड़ा क्योंकि बाहर काम करने वाले परिवार के सदस्यों के वापस लौटने के कारण उनके सीमित संसाधनों पर ज़ोर पड़ रहा था।

डब्ल्यू.जी.डब्ल्यू.एल.ओ. के सदस्यों ने जो कार्यवाही अपनाई उसमें अलग–अलग स्तरों पर सदस्यों द्वारा कई गतिविधियां की जानी थी। पहले उन्होंने नेटवर्क के सदस्यों के बीच खरीफ़ कृषि उत्पादन पर होने वाले प्रभावों और खासकर महिला किसानों पर होने वाले प्रभावों की सामूहिक समझ बनाई, और फिर इस समझ को महिलाओं के संघ और खंड–स्तरीय अर्धन्यायिक कार्यकर्ताओं और महिला सखियों के माध्यम से स्थानीय महिलाओं तक पहुंचाया। डिजिटल संचार साधनों और वर्चुअल बैठकों ने महिलाओं को उनके संघ के नेतृत्वकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चित्र: खरीफ़ की खेती के लिए महिला किसानों को बीज देती महिला किसान सखी कनक – स्वाती, पातड़ी, सुरेन्द्रनगर
(चित्र: डब्ल्यू.जी.डब्ल्यू.एल.ओ.)

महिला किसान सखियों ने १५,००० से अधिक महिला किसानों को संदेशों के माध्यम से रसोई खेती, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए खेती करने, खेती के तरीकों में विवधता लाने और अधिक समय तक खाद्य सुरक्षा के लिए फसलों, ज़मीन को लाभ देने वाली फसलों, हाइब्रिड बीजों का उपयोग न करते हुए स्थानीय, पारंपरिक या उन्नत किस्म के बीज के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में जानकारियाँ उपलब्ध करवायीं। डाँग के दूरस्थ गाँव आह्वा की मीराबेन पढ़ियार को सजीवखेती प्रणाली के विषय पर ऑडीयो संदेश बहुत नवीन लगे – ''हमें बिना कहीं जाए ही बेहद उपयोगी जानकारी मिलती है, जैसे कि प्राकृतिक उर्वरक कैसे बनाए जाएँ''।

और भौतिक स्तर पर, कई महिला किसानों द्वारा व्यक्त की गई ज़रूरत कि वे खरीफ़ ऋतु के पहले खेती के लिए ज़रूरी चीज़ें, बीज, उर्वरक और कीटनाशक नहीं खरीद पाए, तो डब्ल्यू.जी.डब्ल्यू.एल.ओ. ने दानदाताओं और अन्य सामाजिक परोपकारियों से ४२०० महिला किसानों के लिए सहयोग मांगा, विशेषकर एकल महिला किसानों, महिला कृषि मज़दूरों और पलायन से वापस आई महिला किसानों के लिए।

२०१९ में स्थानीय किसानों से प्राप्त किए गए, डब्ल्यू.जी.डब्ल्यू.एल.ओ. के सदस्यों के बीच आपस में बांटे गए और नेटवर्क के अन्य सहयोगियों तथा सहभागियों से लिए गए पारंपरिक देसी बीज की किस्मों से शुरू किए गए बीज बैंक ने खरीफ़ ऋतु में ८५० महिला किसानों को सहयोग दिया। यह सभी लगभग ५००० महिला किसान फ़सल तैयार होने पर, सामुदायिक बीज बैंक को आधे से लेकर दोगुने बीज वापस करेंगी, जिन्हें आने वाली कृषि ऋतुओं में महिला संघ के सदस्य आपस में बांटेंगे और उनका प्रबंधन करेंगे।

महामारी ने छोटे और सीमांत महिला किसानों के सामने सामाजिक, आर्थिक आजीविका और जीवनयापन की चुनौतियाँ लाकर खड़ी कर दीं, जिनमें रीलीफ कार्यक्रम कुछ तो मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल थोड़े ही समय के लिए। सामूहिक रूप से, उपरोक्त हस्तक्षेपों के साथ राहत को मिलाकर, डब्ल्यू.जी.डब्ल्यू.एल.ओ. ने उनके लिए आजीविका पुनर्निर्माण का प्रयास किया, जिससे महिला किसानों को बेहतर पुनर्निर्माण करने में मदद मिली।

✧

थीम: किसान–उपभोक्ताओं के बीच सीधी कड़ियाँ

थानामिर सेब: एकता की मज़बूती (लेखक: रम्या नायर)

थानामिर गाँव माउंट सारामाती, नागालैंड के सबसे ऊंचे पर्वत के नीचे बसा है। यह क्षेत्र यीमखियुंग नागा आदिवासियों का पारंपरिक निवास स्थान है, जो कि कई तरह की प्रकृति–आधारित आजीविकाएँ चलाते हैं, विशेष रूप से झूम कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना, मशरूम इकट्ठे करना, मधुमक्खी पालन और सेब पैदा करना। इस दूरस्थ सीमा के गाँव में पहली बार सेब लाने वाला एक सिपाही था, जिसने चार दशक पहले गाँव के एक बूढ़े को सेब उपहार में दिए और उन्होंने उसका बीजारोपण कर दिया। अब ङ्गङ्गनागालैंड में सेब वाला गाँवङ्गङ्ग के नाम से पहचाने जाने वाले, थानामिर में २०१० से लेकर अब तक आठ सेब उत्सव मनाए जा चुके हैं, जब २०२० की शुरुआत में महामारी का प्रकोप शुरू हो गया।

महामारी के कारण आई चुनौतियाँ

थानामिर भारत–म्यांमार सीमा पर नागालैंड के किफिरे ज़िले में स्थित है और २००८ में यह सबसे नज़दीक के शहर पुंगरों से सड़क से जुड़ा। इस क्षेत्र की दूर–दराज़ और पहाड़ी सड़कें खराब संपर्क का कारण बन जाती हैं, खासकर व्यापार के लिए। थानामिर में सेब उत्सव की शुरुआत स्थानीय नागरिकों और नेताओं ने की जिससे कि पर्यटन और कृषि–अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। पिछले सालों में यह स्थानीय आर्थिक व्यवस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। थानामिर में महामारी के कारण कई सामाजिक–आर्थिक समस्याएं पैदा हुईं – एक ओर जिन छात्रों को घर वापस लौटना पड़ा और कम बिजली और खराब इंटरनेट कनेक्शन की स्थितियों में अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ी, दूसरी ओर दिहाड़ी मज़दूर जो दूसरे इलाकों में जाकर काम नहीं कर पा रहे थे, और वहाँ के निवासियों को ज़रूरी चीज़ें, सेवाएँ प्राप्त करने और शहर में जाकर व्यापार करने में परेशानियाँ आ रही थीं। २०२० में सेब उत्सव खारिज होने के साथ–साथ, यात्रा पर प्रतिबंध होने के कारण थानामिर में आने वाले ग्राहक और पर्यटकों की संख्या भी कम हो गई। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव सेब उत्पादकों पर हुआ, जो वहाँ की जनसंख्या का ६०% हिस्सा है।

महामारी का जवाब

२०२० से पहले के वर्षों में, जैसा मौका मिलता था तो लोग और परिवार खुद सेब बेचते थे। किसान कई वर्षों से इस उम्मीद में सेब उत्पादन कर रहे थे कि एक दिन यह एक बड़ा सामुदायिक स्तर का व्यापार बन जाएगा। लेकिन उनकी योजनाओं में कई बाधाएँ थीं: खराब सड़क, पिछले समय में बाहरी सहयोग पर निर्भरता, और शहरों में जाकर बेचने के लिए रास्ते में दिए जाने वाले विभिन्न कर।

थानामिर निवासी के घर के पीछे बगीचे में सेब के पेड़
(फोटो: लेमचीमोंग यीमखियुंग)

लेकिन, इस समय के दौरान, महामारी के कारण लागू किए गए प्रतिबंधों और कटाव ने थानामिर के निवासियों को सामुदायिक रूप से सेब की बिक्री बढ़ाने के बारे में सोचने का समय दिया। खोई हुई आजीविका की भरपाई करने के अलावा, थानामिर ग्राम छात्र यूनियन के सदस्यों के लिए एक अन्य प्रेरणा का कारण था कि उन्हें २०२३ में आने वाले स्वर्णोत्सव के लिए पैसा इकट्ठा करना था। छात्र यूनियन, ग्राम पंचायत और आम लोगों के विभिन्न समूहों ने समय और संसाधन लगाकर थानामिर सेब की बिक्री के लिए रणनीति बनाने का निर्णय किया। जगह-जगह जाकर सेब का यातायात और बिक्री करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर सेब का प्रचार करना शुरू किया जिससे कि वे ज़्यादा उपभोक्ताओं तक पहुँच पाएँ। सोशल मीडिया की पूर्व जानकारी का उपयोग करते हुए, युवाओं ने इसका लाभ उठाते हुए एक नई नेटवर्किंग प्रणाली बनाई। इसके अतिरिक्त, स्थानीय अखबारों में प्रचार के माध्यम से भी कई उपभोक्ता मिले। लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों के माध्यम से भी शहरों और कस्बों में प्रचार किया जैसे कि दीमापुर, कोहिमा, पुंगरों और किफिरे में। उनकी योजना में सबसे महत्वपूर्ण कदम था कि वे शहरों में अपने उपभोक्ताओं को सीधा उनके घर पर सेब पहुंचाने की सेवा दे रहे थे, जिससे महामारी के अनलॉक चरण में, बेचने वाले और उपभोक्ता दोनों भीड़ भरे बाज़ारों में जाने से बच गए। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ाव भी बनाया, और कुछ उपभोक्ताओं ने कई बार उनसे सेब मंगाए। इस प्रकार बिक्री करने के अंत तक, उनके पास सेबों की आपूर्ति से कहीं ज़्यादा मांग थी! २०२० और २०२१, दोनों वर्षों में वहाँ के निवासियों ने थानामिर में पैदा होने वाली ७-८ किस्मों के ५००-१००० किलो सेब बेचे।

गुड़गाँव किसान बाज़ार (लेखक: मानस अरविन्द)

गुड़गाँव जैविक किसान बाज़ार एक साप्ताहिक बाज़ार है जो वर्ष २०१४ से नियमित तौर पर चल रहा था, जब २०२० में कोविड का लॉकडाउन हो गया। इस प्रयास में गुड़गाँव के आसपास के लगभग २० जैविक किसान गुड़गाँव में रहने वाले ५०० परिवारों से जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन के कारण, यह बाज़ार ऑनलाइन स्तर पर काम करने लगा, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके घर पर ही सब्ज़ियों की टोकरी मिलने लगी। इतने वर्षों में, यह बाज़ार पूरी तरह से मुनाफ़ा-मुक्त और स्वैच्छिक प्रयास रहा है, और अपने मूल्यों पर चलता है।

इस बाज़ार से छोटे और बड़े दोनों तरह के ज़्यादातर स्थानीय किसान जुड़े हैं, बशर्ते कि वे समूह के मूल्यों पर चलने को तैयार हों। बाज़ार में किसान और एग्रीगेटर (जैविक दुकानें) दोनों के स्टॉल लगते हैं। दाम किसान खुद निर्धारित करते हैं।

स्वयंसेवी और कुछ उत्साहित ग्राहक नियमित रूप से खेतों को देखने जाते हैं, और पुष्टि करते हैं कि वे जैविक हैं; समूह जैविक प्रमाणीकरण में न तो विश्वास रखता है और न ही उसे बढ़ावा देता है, और विश्वास के रिश्तों के आधार पर काम करता है। ऐसे मामले भी हुए हैं जहां किसानों ने धोखा किया और उन्हें समूह छोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन जैविक बने रहने का प्रोत्साहन इतना ज़्यादा है कि ऐसे मामले बहुत कम हैं।

मानस अरविन्द, समूह के संस्थापकों में से एक, एक ऑनलाइन समूह का सह-संचालन करते हैं, जिसका नाम है षरीाशीी-ारीज्ञशीी-ळपवळरऽसेसश्रशर्सीीिि. लेा, इसमें पहले से चल रहे किसान बाज़ार शामिल हैं और वे लोग भी जो ऐसा बाज़ार स्थापित करना चाहते हैं।

✧

थीम: ईकोपर्यटन संबंधित गतिविधियों के माध्यम से आजीविका के अवसर बढ़ाना

बड्र्स ऑफ कश्मीर ने ईकोपर्यटन और आजीविका निर्माण के लिए रास्ता दिखाया (लेखक: इरफान जीलानी और ऋत्विका पतगिरी)

बड्र्स ऑफ कश्मीर की स्थापना कश्मीर के गांदरबल ज़िले के काँगन शहर के एक ३२ वर्षीय पक्षी उत्साही इरफान जीलानी ने की थी। इस प्रयास की शुरुआत लॉकडाउन के दौरान की गई जिसका उद्देश्य था पक्षी-प्रेमियों को आकर्षित करना व अन्य पर्यटकों को क्षेत्र के पक्षियों से परिचित कराना। इसके साथ-साथ पर्यावरण-हितैषी और सतत तरीके से आजीविका कमाना।

जीलानी की हमेशा से ट्रेकिंग में रुचि थी और वे विभिन्न ट्रेकिंग समूहों के साथ कश्मीर में ट्रेकिंग अभियानों के लिए जा चुके थे। ङ्कङ्कट्रेकिंग करते हुए, मैं प्रकृति के नज़ारे देखा करता और तस्वीरें लेता था,ङ्कङ्क उनका कहना है, ''पक्षियों की तस्वीरें लेना मेरा जुनून बन गया। मैंने वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया लेकिन मेरा दिल टूट गया जब मुझे पता चला कि स्थानीय लोगों ने पक्षियों पर ज़्यादा शोध नहीं किया है। जो भी शोध उपलब्ध हैं वे विदेशियों ने किए हैं।''

जीलानी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करने से शुरुआत की। उन्होंने कश्मीर घाटी में २४३ अलग-अलग पक्षी प्रजातियों की तस्वीरें लीं जिन्होंने कई प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्षी-प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया।

महामारी के दुष्परिणाम

जब महामारी आई, तो सब घर के अंदर रहने के लिए मजबूर हो गए। पर्यटन कार्यक्षेत्र और ऐसे उद्यमों पर निर्भर समुदायों के लिए लॉकडाउन का समय बहुत मुश्किल समय था। युवाओं को भविष्य की चिंता थी और बेरोज़गारी चरमसीमा पर पहुँच गई। उस वक़्त जीलानी ने एक प्रयास शुरू किया जिसका नाम था ''बर्डिंग फ्रॉम बैल्कनी या बर्डिंग फ्रॉम बैकयार्ड'', मतलब कि घर के छज्जे से पक्षी देखना। ''मेरा उद्देश्य था पक्षी देखने वालों को आकर्षित करना और उन्हें इस क्षेत्र के पक्षियों से परिचित करवाना,'' उनका कहना है, ''इससे उन्हें भी कुछ अलग (पक्षियों की) तस्वीरें लेने और हमारे सोशल मीडिया पोर्टल पर पोस्ट करने का मौका मिलेगा।'' इस प्रयास ने अंततः एक क्लब का रूप ले लिया – बड्र्स ऑफ कश्मीर (बी.ओ.के.)।

जीलानी इस समूह को केवल कश्मीर तक सीमित नहीं रखना चाहते जैसे कि कई अन्य समूह हैं जिनमें भागीदारी काफ़ी कम है। उनका विचार एक व्यापक समूह बनाने का था जो युवाओं के लिए अपने काम का प्रदर्शन करने का एक मंच बने और उन्हें क्षेत्र के सफल व्यवसायी बनने के लिए मार्गदर्शन मिले। ऐसा करने में वे सफल रहे और आज बी.ओ.के. में विभिन्न देशों के चार हज़ार सदस्य हैं।

जैसे-जैसे बी.ओ.के. का विस्तार हुआ, जीलानी को विभिन्न पक्षी-प्रेमियों से पक्षी भ्रमण के लिए कॉल आने लगे। जीलानी को इसमें क्षेत्र के युवाओं के लिए सतत आमदनी पैदा करने का मौका दिखाई दिया। जीलानी ३०-४० युवाओं के साथ काम करते हैं और उन्हें पक्षी-प्रेमियों व अन्य पर्यटकों को गाइड करने के लिए खुद प्रशिक्षित करते हैं। युवाओं को फिर पर्यटक भुगतान करते हैं।

कश्मीर में प्रचुर जैवविविधता है जिसमें पक्षी प्रजातियों की बड़ी संख्या है, और इनमें से कई प्रजातियाँ केवल कश्मीर में ही पाई जाती हैं, जीलानी कहते हैं, ''और बी.ओ.के. के विस्तार के बाद, हमें पक्षी-भ्रमण व प्रकृति-भ्रमण के लिए बहुत अनुरोध आते हैं, जो यूरोप में एक अवधारणा के रूप में उभरा है। इसके बाद हमने कुछ पर्यावरण-अनुकूल भ्रमण शुरू किए जहां हम पक्षी-प्रेमियों को सीधे उनके गंतव्य स्थल पर ले जाते हैं। यह उस क्षेत्र के लोगों के लिए आमदनी का एक ज़रिया बन गया है।''

इरफान जीलानी

इस आमदनी को बनाए रखने के बावजूद, बी.ओ.के. ने महामारी के कारण यात्रियों की संख्या को सीमित रखा है। बाद में इसका विस्तार करके और ज़्यादा पर्यावरणीय रूप से सतत रोज़गार पैदा किया जा सकता है।

स्प्रेड एन.ई. : स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका

(लेखक: शांतनु मुलुक)

स्प्रेड एन.ई. (सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ रुरल ईकोनोमी एण्ड ऐग्रिकल्चर डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट) एक गैर-सरकारी संस्था है जिसकी परिकल्पना है कृषि पद्धतियों को क्रमिक लेकिन स्थिर रूप से रासायनिक से जैविक उत्पादन में परिवर्तित करना। स्प्रेड एन.ई. समूचे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए सतत और समान रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कृषि और खाद्य उद्यमियों को स्थापित करने का काम करता है। इसकी स्थापना गुवाहाटी में वर्ष २०१७ में एक किसान, समीर बोरदोलोई द्वारा की गई, और यह स्थानीय लोगों को स्थानीय स्त्रोतों से खाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इसने छोटे और सीमांत किसानों को उनके घर के बगीचों को जैविक पोषण और औषधीय बगीचों के रूप में विकसित करने में मदद करके

पोषण सुरक्षा में मदद की है और साथ–साथ उनकी आवश्यकता से अधिक उत्पादन को किसान सहकारी समितियों के माध्यम से बेचने में मदद करके उनके लिए सतत आजीविकाएं भी स्थापित की हैं। अपने ग्रीन कमैन्डो (जी.सी.) कार्यक्रम के मध्यम से, इसने परिवर्तनकारियों का एक नेटवर्क स्थापित करने और प्रशिक्षण देने में योगदान किया है, जो शून्य–मूल्य जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं।

कोविड–१९ के लिए प्रतिक्रिया

महामारी के दौरान जो विभिन्न मुद्दे उभर कर आए, उनका समाधान करने के लिए, समीर ने सामुदायिक कल्याण केंद्रों (सी.डब्ल्यू. सी.) के विचार को जन्म दिया: कृषि उत्पादन और खराब स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं का एक बाज़ार।

कॉलोंगपुर गाँव के एक भ्रमण के दौरान वे मोहे फंगचो (एक जी.सी.) द्वारा किसानों को खाद्य वन फ़सल का उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षण दे रहे थे, जहां उन्होंने दो कहानियाँ सुनीं और उनसे उन्हें सी.डब्ल्यू. सी. प्रयास शुरू करने का प्रोत्साहन मिला। उन्होंने जाना कि गर्भवती महिलाओं को सबसे नज़दीकी अस्पताल में ले जाते हुए, १२ बच्चों का जन्म जीप में ही हो गया। मोहे फंगचो ने भी अपनी दुखभरी कहानी बताई जब उन्हें अपनी बीमार माँ को बांस के स्ट्रेचर में पहाड़ी रास्तों से सोनापुर अस्पताल ले जाना पड़ा, और अंततः उनकी माँ की मृत्यु हो गई।

सी.डब्ल्यू. सी. के अंतर्गत, खेत और ग्राम पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टरों को आकर्षित करने की योजना थी। कॉलोंगपुर गाँव के निवासी आगे आए और उन्होंने अपने गाँव में केंद्र बनाने के लिए एक जगह दी और बांस तथा छत बनाने के लिए घास भी दान में दी। केवल १५ दिनों में केंद्र का भवन बन कर तैयार हो गया क्योंकि उनके पास उसे बनाने की विशेषज्ञता और कुशलता मौजूद थी! उचित स्वच्छता सुविधाओं से युक्त बांस की कुछ झोपड़ियाँ बनाने के लिए उन्होंने मदद मांगी जहां डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था की जा सके।

उन्होंने कृषि–पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियों की योजना तैयार की: नारंगी के बगीचों और रोज़ेल खाद्य वनों में ट्रेल, स्थानीय खाना, खेतों में रहने और कैम्पिंग की व्यवस्था। इसके बदले में, किसान डॉक्टरों और पशु–चिकित्सकों से अनुरोध करेंगे कि वे समुदाय में ३ घंटे की सेवा दें।

कॉलोंगपुर में सी.डब्ल्यू. सी. की शुरुआत सितंबर २०२० में हुई। गाँव की जनसंख्या ७००–८०० है, और सभी अमरी करबी आदिवासी समुदाय से हैं। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है।

डॉ. स्वस्तिका पद्मापति, असम की एक युवा डॉक्टर, इस गाँव के किसानों को सेवा देने वाली पहली डॉक्टर थीं। उनके आने से स्प्रेड एन.ई. और किसानों को आत्मविश्वास मिला। जी.सी. के नेटवर्क और सोशल मीडिया के उपयोग ने इस विचार का प्रचार करने में मदद की, जिससे कई युवा डॉक्टरों और इच्छुक सेवा प्रदाताओं से जुड़ाव बना। स्वयंसेवियों के रूप में भी युवा डॉक्टर इस समुदायों द्वारा शुरू किए गए अभियान के सहयोग के लिए आगे आए।

सामुदायिक कल्याण केंद्र में डॉ. स्वस्तिका पद्मापति
असम की एक युवा डॉक्टर

समीर का विचार था कि इसे आत्म–निर्भर बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने गाँव कि महिला किसानों को औषधीय पेय बनाने का प्रशिक्षण दिया जैसे कि पौष्टिक–औषधीय पौधे रोज़ेल से औषधीय चाय बनाना। केंद्र ने अपना पहला बिक्री उत्पाद तैयार किया, रोज़ेल औषधीय चाय, जिसकी ब्रांड को नाम दिया हंसेरोंग रोज़ेल चाय। महिला समूह ने रोज़ेल औषधीय चाय की बिक्री से लगभग रु.६५,००० का कोश तैयार किया, जिसमें बाहर से कोई निवेश नहीं था।

अपने हाल के प्रयास, ङ्कङ्घधीमा और सक्रीय जीवन कार्यक्रमङ्कङ्घ के अंतर्गत, वे धीमे फैशन उत्पाद बेचने की ओर देख रहे हैं, जैसे कि हथकरघे पर बने कपड़े, जो कि सशक्तिकरण में मदद कर सकते हैं। वे पारंपरिक हथकरघों और अहिंसा सिल्क का उपयोग करते हैं जिसमें कपड़ा बनाने के लिए काफ़ी कम पानी का उपयोग होता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने उत्पादनों का प्रचार किया और भारत के विभिन्न भागों में डिलीवरी के लिए स्पीड–पोस्ट का। यह केंद्र न केवल स्वास्थ्य देखरेख, बल्कि कृषि–पर्यटन के माध्यम से आजीविका सुरक्षा और सेहतमंद खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी मदद करते हैं। एक तरह से, यह केंद्र स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के अभिसरण बिन्दु हैं।

✧

थीम: सूक्ष्म वनोपज तक पहुँच पर आधारित आजीविकाएँ और वन संसाधन; सामुदायिक वन प्रबंधन

ग्राम सभाओं के नेतृत्व में प्रशासन
(लेखक: केशव गुरनुले)

''ग्राम सभा ने सभी परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, जिसमें सबसे हाशिये के समुदायों की आवश्यकता की खाद्य आपूर्ति का अनुमान भी शामिल था। उन्होंने लोगों के लिए निशुल्क और सूखे पके खाने की व्यवस्था की। घर वापस आने वाले पलायनरत मज़दूरों की बड़ी संख्या के कारण, ज़िला केंद्र पर क्वॉरन्टीन सुविधा बनाई गई और मज़दूरों को खाना उपलब्ध करवाया गया।'' सृष्टि – एक सामुदायिक सहयोग संस्था – के सदस्य केशव ने बताया कि किस प्रकार ग्राम सभाओं ने कोविड प्रबंधन योजनाओं का नेतृत्व किया।

अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के राजनन्दगाँव ज़िले के नौ विकास खंडों में से एक है। इस खंड में, मुख्यतः जनसंख्या आदिवासी है (गोंड, कंवर, हलबा और बैगा) जो कि वनों और कृषि पर निर्भर करते हैं। वर्ष २०१२–१३ में, पांगरी, खैरी, केसलदबारी, पड़की, सोनोली और दुर्रेटोला गांवों को संयुक्त वन प्रबंधन कमिटी (जे.एफ.एम.सी. में वन विभाग और वन समुदायों दोनों के सदस्य होते हैं) के नाम पर उनके सामुदायिक वन अधिकार मान्यता प्रमाणपत्र मिले जिसके अंतर्गत सूक्ष्म वनोपज, चराई और निस्तार (राजाशाही और जमींदारी प्रणाली के समय से मान्यताप्राप्त सामुदायिक अधिकार) अधिकार मिले।

ग्राम सभाओं ने जे.एफ.एम.सी. योजना को अस्वीकार कर दिया और स्वतंत्र रूप से सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन कमिटियाँ (सी.एफ.आर.एम.सी. पूरी तरह से आदिवासियों और वन निवासियों की कमिटी होती है जो सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है) बनाईं, जिसके माध्यम से वे अपने अधिकारों की पालना, वनों में गश्त लगाना और सी.एफ.आर. संरक्षण का काम कर सकते थे।

कोविड–१९ लॉकडाउन के दौरान, समुदाय ने प्रबंधन योजना के अनुसार अपने सी.एफ.आर. अधिकारों का उपयोग किया जिन्हें ग्राम सभाओं ने पहले से पारित किया हुआ था। उसी समय ग्राम सभाओं ने कोविड लॉकडाउन प्रशासन प्रक्रिया लागू करनी शुरू की। सरकार और पुलिस विभाग, वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने ग्राम सभा द्वारा शुरू किए गए प्रयास में बाद में सहयोग दिया। वास्तव में, स्थानीय प्रशसन ने ग्राम सभाओं की योजनाओं की सराहना की जिनमें स्थानीय और वन–आधारित खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बाज़ारों में भीड़ होने से भी सुरक्षा हुई। योजनाओं में वन सुरक्षा और संरक्षण, सूक्ष्म वनोपज एकत्रीकरण और बिक्री, खाद्य सुरक्षा और वितरण और आजीविका प्रबंधन शामिल था।

जब कोविड–१९ को महामारी घोषित कर दिया गया और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा होने वाली थी, तब ग्राम सभाओं ने सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया। लेकिन, उसके तुरंत बाद, लोगों को राशन, दवाएँ और सब्ज़ियाँ लाने में परेशानी आने लगी। इसलिए, ग्राम सभाओं ने निर्णय लिया कि वे एकजुटता के साथ इस समस्या का सामना करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे घरों के आसपास उगने वाले औषधीय पौधों, खेत और वन से प्राप्त होने वाली सब्ज़ियों के वितरण के लिए एक प्रणाली बनाएँगे और गाँव वालों को व्यापारिक बाज़ारों में जाकर यह सब खरीदने से प्रतिबंधित करेंगे। केवल गाँव के दुकानदारों को कुछ आवश्यक किराने का समान और दवाइयाँ खरीदने के लिए पास जारी किए गए।

सी.एफ.आर. प्रबंधन योजना और रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत, एक वन तालाब और एक निस्तार तालाब बनवाया गया और इन तालाबों में मछलीपालन व्यवसाय शुरू किया गया। उसी के साथ–साथ, जिमीकंद, कोचईकंद और केवकन्द जैसे स्वदेशी पौधे लगाए गए।

समुदाय सुरक्षा के लिए उचित दूरी बनाकर अपना नियमित सी.एफ. आर. प्रबंधन काम करते हुए

सी.एफ.आर.एम.सी. ने वन संसाधनों के दैनिक एकत्रीकरण के लिए गाँव वालों/ स्थानीय लोगों को पहचान पत्र और पास जारी किए। रोज़मर्रा के उपयोग के लिए, उन्होंने तय किया कि हर तोक की तीन महिलाएँ और तीन पुरुष वन के अलग–अलग भाग में जा कर फल, फूल, कंद, सब्ज़ियाँ, जलाऊ लकड़ी और चारे की घास ला सकते हैं। कमिटियों ने तस्करी मुक्त वन क्षेत्रों से एकत्रीकरण के लिए एक योजना बनाई। कोविड–१९ के विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए थे कि वे स्वास्थ्य जनकारी के नारे सार्वजनिक जगहों पर पेंट करवाएँ और लाउड्स्पीकर के माध्यम से जानकारियाँ बांटें।

बाहरी पलायन में गिरावट

(लेखक: प्रतिभा शिंदे और सतरेसेन मोतिराम)

नंदुरबार ज़िले में महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा एकड़ ज़मीन पर सी.एफ. आर. को मान्यता दी गई है, जहां अप्रैल २०१८ में समुदायों के पास २,१६,७२३.१० एकड़ ज़मीन पर पट्टे थे। वनों में प्रचुर मात्रा में भूतया (गोंद), महुआ फूल, कुड्डापह बादाम (चार) के पेड़ हैं और सी.एफ.आर. प्रबंधन योजना के अंतर्गत, सी.एफ.आर.एम.सी. और पेड़ लगा रही हैं जिनसे वन निवासियों की आजीविकाओं के लिए सहयोग हो सके।

समुदाय सूक्ष्म वनोपज संगठनों में संगठित किए गए हैं, जिनके सदस्य वनोपज इकट्ठा करते हैं। सी.एफ.आर.एम.सी. प्रत्येक संगठन से सूक्ष्म वनोपज इकट्ठा करती हैं और उन्हें प्रतिस्पर्धी मूल्य तथा बोनस देती हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि वे सूक्ष्म वनोपज को बिचोलियों को न बेचकर सीधा व्यापारियों को बेचते हैं। कमिटी ने मार्गदर्शिका भी बनाई है जिसके अंतर्गत वे उन लोगों को सहयोग करते हैं जो कोई समस्या होने के कारण किसी वर्ष वनोपज इकट्ठी नहीं कर पाते, जिससे कि सीज़न में सभी के लिए आजीविका सुनिश्चित की जा सके।

प्रतिभा शिंदे, स्थानीय गैर–सरकारी संस्था लोक समन्वय प्रतिष्ठान की सदस्य, कहती हैं ''२०१६ तक बहुत सारे लोग काम के लिए नंदुरबार ज़िले से बाहर जाते थे। कामगार छः महीनों के लिए कृषि मजदूरी के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब यह रुक गया है। कोविड–१९ लॉकडाउन के दौरान, गांवों में रोज़गार था: वनोपज इकट्ठा करना, रोज़गार गारंटी के माध्यम से पौधरोपण करना और सी.एफ.आर.एम. सी.के माध्यम से सिंचाई व अन्य उपयोग के लिए जल भंडारण ढांचे और तालाब बनाना। वास्तव में, जल प्रबंधन की एक पूरी योजना, जो तोरणमल क्षेत्र पर केंद्रित है, वह इन कमिटियों द्वारा लागू की जा रही है। मज़दूरों को औसतन रु.२५०–३०० प्रतिदिन मज़दूरी मिली। गाँव में रहने के फायदे हैं, वे अपने जंगलों की सुरक्षा कर पाए, और अपने बच्चों की शिक्षा का भी प्रबंध कर पाए।''

कोविड–१९ लॉकडाउन के दौरान, नंदुरबार की सी.एफ.आर.एम. सी. संगठित थीं और उन्होंने इंदौर और मुंबई जैसे शहरों को रु.७० प्रति किलो की दर से गोंद बेचा। गाँव वालों को गोंद इकट्ठा करने के श्रम के लिए रु.५०/किलो दिया गया और रु.१०/किलो मुनाफे के बोनस के रूप में। उन्होंने महुआ भी रु.५०/किलो की दर से बेचा और गाँव वालों को रु.४०/किलो इकट्ठा करने और रु.५/किलो बोनस के रूप में दिया गया। लोग लॉकडाउन के दौरान भी वनोपज से हुई अपनी आमदनी लेकर गाँव की दुकानों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद पा रहे थे।

पिछले कुछ वर्षों में, समुदायों ने ऐसे पेड़ों की प्रजातियाँ लगाई हैं जिन से वनोपज इकट्ठी की जा सकती है। इस लॉकडाउन के दौरान, गाँव वालों ने आम के पेड़ आदि लगाए, जो भविष्य में आजीविकाओं और खाद्य सुरक्षा के लिए लाभदायक हो सकते हैं। इस वर्ष समुदायों ने वनोपज इकट्ठी की है, श्रम के लिए पैसे मिले हैं, और महुआ तथा गोंद बेचने से हुए मुनाफे से बोनस भी दिया गया है। कुछ अन्य सूक्ष्म वनोपज को बेचने के लिए, कमिटियाँ बेहतर दामों का इंतज़ार कर रही हैं।

थीम: लॉकडाउन के समय का सदुपयोग

सामुदायिक जुड़ाव चुनौती – युवाओं में नागरिक जागरूकता और नेतृत्व विकास

(लेखक: पंखुरी जैन, केजल सावल और अरविन्द नटराजन)

समुदायों ने सी.एफ.आर. क्षेत्रों में स्थानीय प्रजातियाँ लगाईं

द ब्लू रिबन मूवमेंट (बी.आर.एम.) मुंबई का एक युवा–नेतृत्व का आंदोलन है जो एक बेहतर दुनिया के लिए युवा नेतृत्व विकास और जुड़ाव भरे समुदाय बनाने पर काम करता है। यह गहन लोकतंत्र के मूल्यों पर विश्वास रखता है और १००% सहमति–पूर्ण निर्णय प्रक्रिया से काम करता है। द कम्यूनिटी कनेक्ट फ़ेलोशिप (सी.सी.एफ.) बी.आर.एम. का प्रमुख कार्यक्रम है। मुंबई के युवाओं को रचनात्मक कार्यवाही में शामिल करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था जिसमें शामिल अध्येताओं में नागरिक सहभागिता और पारस्परिक कुशलताएँ बढ़ाई जा सकें।

महामारी के कारण २०२० में इस फ़ेलोशिप को स्थगित कर दिया गया और इससे टीम को फ़ेलोशिप के बारे में दोबारा सोचने, चिंतन करने, पुनः रूपरेखा बनाने और पुनर्गठित करने का मौका मिला। युवाओं के नागरिकता सफ़र को जारी रखने और मनोरंजन तथा सीखने के साथ युवाओं को सार्थक रूप से शामिल करने के लिए, बी.आर.एम. ने दो सप्ताह की एक ऑनलाइन नागरिक चुनौती शुरू की जिसका नाम था कम्यूनिटी कनेक्ट चैलेंज (सी.सी.सी.) और इसका उद्देश्य था मुंबई में स्थानीय सक्रीयता के लिए युवा नेतृत्व और नागरिक समझ का विकास करना। भागीदारों के लिए सी.सी.सी. का सफ़र एक नया दृष्टिकोण था क्योंकि वे मुंबई शहर को एक अलग नज़र से देख रहे थे। इसमें शहर के इतिहास और संस्कृति को देखते हुए, भागीदारों को मुंबईकर की उनकी पहचान से दोबारा जुड़ने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त उन्हें सक्रीय नागरिक के रूप में छोटे–छोटे कदम उठाने में भी मदद मिली।

सी.सी.सी. में चार कुशलताओं के निर्माण और २१ गतिविधियां पूरी करना शामिल था। इन सत्रों का ज़ोर एक भौगोलिक जगह से आगे, एक समग्र नज़रिए से मुंबई के साथ आशयपूर्ण रिश्ता बनाने पर था। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, भागीदार शहर के विभिन्न पहलुओं से जुड़ते हैं: उसके खान–पान, सार्वजनिक जगहें/स्थल, उसे परिभाषित करने वाले क्षण या घटनाएँ आदि। इसमें मुंबई की नागरिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को समझना तथा संवाद कुशलताएँ बढ़ाना जैसे कि सुनना और समुदाय में काम करने के लिए उपयोगी कुशलताओं का निर्माण भी शामिल था।

लेकिन असल ''चुनौती'' थी सत्र खत्म होने के बाद की गतिविधियां पूरी करना। २१ गतिविधियों के ज़रिए भागीदारों को सत्रों में सीखी चीज़ों का व्यावहारिक अनुभव मिला। कुछ गतिविधियाँ इस प्रकार थीं – अपने घर पर काम वाली से बात करके पता करना कि कोविड–१९ का उन पर क्या प्रभाव हुआ, कोई नागरिक शिकायत दर्ज करना, स्थानीय नगरपालिका वार्ड में उपलब्ध सुविधाओं को समझना या ऐसे ही दयालुता का कोई एक काम करना।

एक अध्येता ने अपने घर की कामवाली, ड्राइवर, और उनके परिवारों को सिखाया कि नागरिक शिकायत कैसे दर्ज की जाती है। उसने उन्हें उनकी जल आपूर्ति की शिकायत दर्ज करने में मदद की, जिसकी वजह से वे काफ़ी समय से परेशान थे। उनके बच्चे भी इसमें शामिल हो गए, और उन्हें भी लॉकडाउन के दौरान कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला।

सी.सी.सी. का पहला जत्था जुलाई २०२० में शुरू हुआ। दिसंबर तक ४ जत्थे और ६३ भागीदारों ने कार्यक्रम पूरा किया और उन्होंने कार्यों की एक विस्तृत शृंखला पर काम किया। इस कार्यक्रम से युवा भागीदारों को उम्मीद और आत्मविश्वास मिला कि वे भी बदलाव ला सकते हैं। ऐसे समय जब वे अपने घरों पर खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहे थे, सी.सी.सी. उनके लिए अपने विचार साझा करने

और अपनी जैसे सोच रखने वाले लोगों से मिलने का मंच बन गया। उम्मीद है कि यह छोटा सफ़र युवाओं में अपने शहर के प्रति अपनेपन की व्यापक भावना को प्रज्वलित करने में मदद करेगा और उनके अंदर उन समुदायों के लिए कुछ करने की भावना जागेगी, जिन्होंने उनका पोषण किया है।

महामारी में भी सीखना जारी: उत्तराखंड के युवा प्रकृति गाइड

(लेखक: संजय सोंढी, केसर सिंह, ऋत्विका पतगिरी)

वनों की कटाई के साथ-साथ कृषि उत्पादकता में आ रही गिरावट के कारण हिमालय के ज़्यादातर कृषि एवं वन आधारित समुदाय अपनी पारंपरिक आजीविकाओं से दूर होते जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्र में बाहरी-पलायन और गरीबी बढ़ रही है। तितली ट्रस्ट और सेंटर फॉर ईकालजी डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च (सिडार) द्वारा चलाए जा रहे प्रकृति गाइड कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूबर २०१९ में, प्रकृति से जुड़े ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के रूप में उत्तराखंड के तीन भूदृश्यों में की गई: मसूरी-बेनोग, झिलमिल झील - थानो, और मुक्तेश्वर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पारिस्थितिकीय और आर्थिक सततापूर्ण आजीविका के रूप में उत्तराखंड के तीन गाँव-समूहों में सक्षम और समर्पित प्रकृति गाइड तैयार किए जाएँ, जिसके लिए प्रकृति-आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए।

केसर सिंह

प्रशिक्षण लेने वाले ज़्यादातर ऐसे परिवारों से हैं जो प्रकृति से जुड़े गाइड के काम को कृषि व गैर-कृषि गतिविधियों से होने वाली आमदनी के पूरक के अवसर के रूप में देखते हैं। इनमें से ज़्यादातर कृषि या यातायात और आतिथ्य जैसे कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वे उत्तराखंड में उपलब्ध प्रकृति से जुड़े आजीविका के अवसरों के बारे में बहुत उत्साहित हैं। महामारी से पहले, हर अभ्यास सत्र में आम तौर पर २-३ सप्ताह के अंतराल में ३-४ घंटे के लिए फील्ड में प्रशिक्षण होता था। फील्ड प्रशिक्षण में पक्षियों की पहचान करना और अन्य प्राकृतिक इतिहास के मुद्दे शामिल होते हैं। प्रशिक्षण लेने वालों को पौधों और जानवरों की पहचान करने के लिए गाइडबुक इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है।

महामारी से पहले, सभी प्रकृति गाइडों के लिए अक्टूबर २०१९ में अभिसंस्करण किया गया। आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च २०२० तक चल रहे थे जब महामारी ने प्रकृति के साथ मनुष्यों के रिश्तों को बदल कर रख दिया।

महामारी के दुष्परिणाम

जब महामारी की शुरुआत हुई, तो बाकी सब चीज़ों की तरह पर्यटकों ने भी मध्य-मार्च तक आना बंद कर दिया। लेकिन प्रकृति गाइड कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। लॉकडाउन के पहले ३ माह में कोई अभ्यास सत्र या फील्ड प्रशिक्षण नहीं हुआ। लेकिन प्रशिक्षण और प्रकृति के बारे में सीखना जारी रहा। हाँलाकि भागीदार मध्य-मार्च से जून तक एक-दूसरे से मिल नहीं सके, लेकिन वर्चुअल प्रशिक्षण जारी रहा। नवाचार और रचनात्मकता के माध्यम से, प्रकृति-शिक्षा ऐसे समय में भी संभव हो पाई, जब एक-दूसरे से मिलना भी संभव नहीं था!

''पहले हम पक्षियों पर ही ध्यान देते थे, लेकिन अब, बदलते समय के साथ, हमने वनस्पतियों और तितलियों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है,'' केसर सिंह बताते हैं, जो कि प्रकृति गाइड कार्यक्रम के साथ २०१४-१५ से जुड़े हुए हैं। केसर सिंह और तौकीर आलम लोढ़ा, जो क्रमशः मसूरी और झिलमिल भू-दृश्यों में रहते हैं, दोनों ने लॉकडाउन के दौरान प्रोग्राम को संभालने और जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंह और तौकीर दोनों स्थानीय निवासी हैं लेकिन उन्होंने प्रभावकारी तरीके से अपना ज्ञान बांटा, कार्यक्रम को जारी रखा, और संसाधन व्यक्तियों की भूमिका निभाई है। वे भागीदारों के व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से सभी के साथ निरंतर संपर्क में रहे। ''हाँलाकि हम एक-दूसरे से मिल नहीं पाए, हमारे सीखने की प्रक्रिया जारी रही। कभी मैं अपने कमेरे से फोटो लेकर समूह में पोस्ट करता, और कभी मैं इंटरनेट से उन्हें डाउनलोड करता। लेकिन हमारी प्रक्रिया रुकी नहीं,'' केसर सिंह ने बात जोड़ते हुए कहा।

प्रशिक्षणार्थियों से भी कहा गया कि वे अपने घर के आसपास की पक्षियों की गिनतियों के आधार पर बनाई पक्षी-सूचियां, पौधों और तितलियों के पोस्ट करते रहें। वर्चुअल व्हाट्सएप समुदाय में पक्षियों, तितलियों की पहचान और पेड़ों के घटनाविज्ञान पर प्रश्नोत्तरी चलती रही।

✦✦

४. अन्य देशों से तन्यकता की कहानियाँ

कोविड–१९ की प्रतिक्रिया में एकजुटता और तन्यकता बढ़ाने के लिए हमारी पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करना

(लेखक: साइमन मितम्बों)

थारका क्षेत्र, जिसे पारंपरिक रूप से थिगुरु इरी जुकी (मधुमक्खियों का क्षेत्र) के नाम से जाना जाता है, माउंट केन्या पहाड़ियों की तलहटी और ताना नदी के बीच बसा है। यह अर्ध–शुष्क क्षेत्र जैविविधता हॉटस्पॉट है जहाँ विशिष्ट रूप से तराई झाड़ियाँ और कई पहाड़ी–शृंखलाएँ पाई जाती हैं।

हाँलाकि थारकाओं की बहुत समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएँ थीं – समुदाय के बूढ़ों का गहरा पारिस्थितिकीय ज्ञान उनके प्रशासन तंत्र का केंद्रबिन्दु था – लेकिन इन परंपराओं को तेज़ी से नष्ट किया जा रहा है। इसका कारण है सरकार और बाहरी एजंसियों द्वारा क्षेत्र में गैर–कल्पित परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाना, जिनके अतर्गत ऐसे आजीविका कार्यक्रम और बीजों को बढ़ाया जा रहा है जो यहाँ की स्थितियों के अनुकूल नहीं हैं। पारंपरिक प्रशासन प्रणाली के साथ–साथ परंपरागत कानूनों को मिटा दिया गया है जो पेड़ों की कटान, जानवरों के शिकार, और जल स्त्रोतों के बहुत नज़दीक खेती करने को नियंत्रित करते थे। इस सब के परिणामस्वरूप समुदाय महामारियों और जलवायु व्यवधानों के प्रति और ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं।

२०१३ में स्थापित, द सोसाइटी फॉर ऑल्टरनेटिव लर्निंग एण्ड ट्रांसफॉर्मेशन (साल्ट) थारका आदिवासी समुदाय के पारंपरिक कानूनों के अंतर्गत स्थापित किए गए सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय प्रशासन संस्थानों का एक समुदाय–आधारित नेटवर्क है। साल्ट समुदाय के बीच एकजुटता और तन्यकता बनाने के उद्देश्य से सांस्कृतिक प्रथाओं और समारोहों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहा है।

समय के साथ–साथ, एक बार फिर पेड़ों की कटान, जानवरों का शिकार, और जल स्त्रोतों के बहुत नज़दीक कृषि न करने पर नियंत्रण करने वाले पारंपरिक कानूनों का सम्मान किया जाने लगा है और उनका पालन भी हो रहा है। पवित्र प्रकृतिक स्थलों – जो कि जैविविधता बहुल आध्यात्मिक महत्व रखने वाले क्षेत्र हैं – की भूमिका धीरे–धीरे पुनर्जीवित की जा रही है और अब, यह स्थल संस्कृति, खाद्य संप्रभुता, और पारिस्थितिकीय तंत्रों की सुरक्षा के केंद्र बन रहे हैं।

समुदाय के बूढ़े याद करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने कोविड–१९ जैसी महामारियों और प्लेग का सामना किया। ऐसी घटनाओं में प्रतिक्रिया करने के उनके अपने पारंपरिक तरीके हैं जो कारण हैं कि थारका लोग अभी भी मौजूद हैं – विशाल टिड्डियों के झुंडों के खड़ी फसलों पर आक्रमण और चेचक जैसी बीमारियों के बावजूद जिन्होंने पहले भी समुदाय के लिए खतरे पैदा किए हैं।

इस प्रकार के खतरों की प्रतिक्रियाओं में से एक अनुष्ठान है मुरीरा। यह एक असाधारण अनुष्ठान है, जिसे तभी किया जाता है जब समुदाय पर किसी बीमारी या महामारी का खतरा होता है। मुरीरा थारका शब्द कुरीरा से जनित है, जिसका मतलब है बचाना, रोकना, निकालना।

तन्यकता पर चर्चा करते समुदाय के सदस्य (फोटो आभार: साल्ट)

पारंपरिक रूप से थारका के बूढ़े मुरीरा अनुष्ठान किया करते थे, जब उन्हें पता चलता था कि आसपास के क्षेत्रों से ऐसे खतरे थारका क्षेत्र में आने की संभावना है। बूढ़े सब लोगों को इकट्ठा करते थे और खतरे के बारे में जागरूकता फैलाते थे, कि वह खतरा कहाँ से आ रहा है, वे चिंतित क्यों हैं, और इस प्रकार प्रमुख जानकारियाँ बांटते थे और उससे प्रभावित होने की संभावना को कम करते थे।

जब कोविड–१९ महामारी केन्या में तेज़ी से फैलने लगी, बूढ़ों ने समुदाय को इकट्ठा किया और मुरीरा अनुष्ठान किया। यह पहली बार थी, जब ईसाई और परंपरावादी भी इस अनुष्ठान में शामिल हुए। एकजुटता में उनके शामिल होने से समुदाय को महामारी से मिले झटके से राहत मिली।

यह अनुष्ठान लोगों को साथ लाता है – शारीरिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से – कि वे एक दूसरे के कल्याण और स्वास्थ्य पर ध्यान दें और उसके साथ–साथ खतरों से खुद को बचाएँ। यह लोगों को थारकाओं के रूप में अपनी पहचान और अपनी मातृभूमि के प्रति उनकी जिम्मेदारियों याद दिलाने में मदद करता है। यह जगहें समुदाय के ज्ञानी बूढ़ों को सुनने की जगह बन जातीहैं। यह एक सूचक है कि समुदाय अपनी ज़मीन में हुए नुकसान के इतिहास का रुख मोड़ रहा है।

समुदाय स्थानीय बीजों की तन्यकतापूर्ण किस्मों को वापस लाने के लिए भी काम कर रहा है। पिछले पाँच से छः वर्षों में, बीज विविधता, सामुदायिक स्तर पर एक–दूसरे के साथ बीज बांटने, और इन बीजों को कैसे उगाना, पकाना, बचाना, और भंडारण करना है इसके ज्ञान के आदान–प्रदान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यह बीज स्थानीय स्थितियों में अच्छी पैदावार देते हैं और बदलते हुए जलवायु स्वरूपों के प्रति लचीले भी हैं। पारंपरिक बीज और प्रथाओं के पुनर्जीवन ने समुदाय की मूल भरण–पोषण की आवश्यकताओं के लिए बाहरी बाज़ार पर निर्भरता कम करने में भी मदद की है।

साल्ट के साथ काम करने के कारण, समुदाय ने कानूनी मान्यता प्राप्त करने और जैविक–सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा के लिए पारंपरिक कानूनों का दस्तावेज़ीकरण भी जारी रखा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुदायों के साथ किए जा रहे काम राजनैतिक निर्णय प्रक्रिया के हर स्तर में योगदान और प्रभाव डाल सकें, साल्ट राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, और वैश्विक प्रक्रियाओं के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ाव बनाए रखने के प्रति समर्पित है।

संपर्क: साइमन मितम्बों (smitambo@yahoo.com
mailto:smitambo@yahoo.com>)
SALT (<https://saltnet.org/chumvi/)

जीवन के बीज, जल का उत्पादन

(लेखक: लीना मरसेला मेनेसेस कबरेरा)

वैले डेल काऊका (काऊका घाटी) कोलम्बिया में स्थित, मॉन्टानिटास उपनगरी इस क्षेत्र के शुष्क परिस्थितिकीय तंत्र से पैदा हुई जल की कमी की एक जटिल वास्तविकता में जी रही है। इस कमी को कार्टन कंपनी ऑफ कोलम्बिया द्वारा कागज़ के उत्पादन के लिए लगाए गए चीड़ और नीलगिरी के पेड़ों ने और बढ़ा दिया है। इस कंपनी पर पहले भी जंगलों की कटान, प्राकृतिक परिस्थितकीय तंत्रों के विनाश, और क्षेत्र में अर्ध–सैन्यवाद के हितैषी होने के आरोप लग चुके हैं (अलज़ाते, २०१७)।

मॉन्टानिटास समुदाय ने ऐतिहासिक स्तर पर कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पानी की कमी का समाधान करने के लिए संघर्ष किया है। एक छोटी नहर से हर १५ दिन में पानी की आपूर्ति की जाती है और परिवारों को दैनिक उपयोग के लिए इसे घड़ों और टंकियों में भर कर रखना पड़ता है।

इन कठिनाइयों के चलते, समुदाय, नागरिक समाज संस्थाओं की मदद से, एक सामूहिक प्रक्रिया में एकजुट हुआ है, जिसके अंतर्गत वे ऐसी प्रक्रियाओं का विकास करने पर ध्यान दे रहे हैं जो उनके क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को हल करने में मदद करेंगी।

सुरकोमुन और यूनका वासी फाउंडेशन ऐसी संस्थाएँ हैं जो ग्रामीण सतत विकास के लिए जैविक कृषि, स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरणीय शिक्षा, और सामाजिक तकनीकों पर काम कर रही हैं। २०१४ में उन्होंने मॉन्टानिटास समुदाय के साथ काम करना शुरू किया। साथ मिलकर, वे जल–आधारित मुद्दों, किसानों के प्रशिक्षण, और जैविक कृषि तकनीकों तथा बारिश के पानी को संजोने पर ध्यान देने वाली संस्थागत जगहों को बढ़ावा दे रहे हैं।

मॉन्टानिटास में, इस रिश्ते के कारण एसोसिएशन ऑफ ऐग्रो–एनवायरनमेंटल रुरल कम्यूनिटीज़ (अकोरा) का औपचारिक रूप से जन्म हुआ जिसमें ३० परिवार शामिल हैं। अकोरा ने एक कार्यकारी योजना तैयार की है जिसमें जल–संबंधित मुद्दों और समुदाय के रूप में इकट्ठे अपने सपनों को साकार करने के लिए वैकल्पिक समाधान दिए गए हैं।

अकोरा के काम से एकत्रित पैसे से कई परिवार कृषि और घरेलू उपयोग के लिए अपने घरों में ज़ामोरानो टंकियाँ (जल भंडारण टंकियाँ) लगवा पाए हैं। दस परिवारों के पास ७,००० लीटर की टंकियाँ हैं और कई परिवारों के पास प्लास्टिक की ३,५०० लीटर की टंकियाँ हैं। इनका प्रबंधन प्रत्येक परिवार के योगदान और विभिन्न गतिविधियों में एसोसिएशन द्वारा बचाए गए पैसों से सार्वजनिक संस्थान करते हैं।

''हमने हमेशा इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है। अकोरा के प्रयास से, हम बारिश के पानी के भंडारण के लिए ज़ामोरानो टंकियाँ लगाने में कामयाब हो पाए हैं'', निलबा मुनोज़ का कहना है जो कि इस संस्था को स्थापित करने के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं में से एक हैं और उन्होंने एक बेहतर जीवन के लिए समुदाय को संगठित करने के अथक प्रयास किए हैं। यह काम मुश्किल है लेकिन संस्था उम्मीद बनाए रखने और जीवन की संभावनाएं पैदा करने के लिए रोज़मर्रा की समस्याओं के ठोस समाधान को आगे बढ़ाने पर जोर देती है।

कोविड–१९ महामारी समुदाय के लिए एक मुश्किल समय रहा क्योंकि वे अपनी नियमित बैठकें नहीं कर पाए और न ही अपने सामूहिक काम ही कर पाए। योजनाओं को स्थगित करना पड़ा, परिवार अकेले पड़ गए और समुदाय के कामों की गतिशीलता को रोकना पड़ा।

लेकिन, टंकियों में भरे बारिश के पानी से समुदाय अपने लिए खाना पैदा कर पाए, जिसे आसपास के क्षेत्रों में भी पहुंचाया गया जहाँ खाने की कमी हो रही थी। कई पलायन कर गए लोग जो वापस गांवों में लौटे, उन्होंने ज़मीन पर काम करने के इस अवसर का लाभ उठाया

और उन्हें अहसास हुआ कि उन्हें इस ज़मीन का ध्यान रखना चाहिए – क्योंकि जब और कुछ काम नहीं करता, तब यही उनका पोषण करती है ।

पानी उपलब्ध होने के कारण, मवेशियों और पक्षियों, जैसे कि मुर्गियाँ, बत्तख और सूअर, को पालना भी बढ़ रहा है। यह परिवारों की खाने की ज़रूरतें और ज़रूरत से अधिक होने पर बिक्री करने से आर्थिक आमदनी की ज़रूरत भी पूरी कर रहा है। अब इससे जुड़े लोगों ने प्रशिक्षण बैठकों का प्रस्ताव दिया है जिससे कि वे बाहरी निवेश और विदेशी बाज़ार पर अपनी निर्भरता कम कर सकें।

समय के साथ एसोसिएशन ने महामारी के दौरान मिलने के तरीके भी निकाल लिए हैं। २०२१ में, बैठकें आयोजित की गईं, जिससे संस्थागत काम दोबारा शुरू हो पाया। समुदाय को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लेकिन उनकी तन्यकता ने अनूठी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया, जैसे कि शहरों में किसान बाज़ार और स्थानीय खाद्य

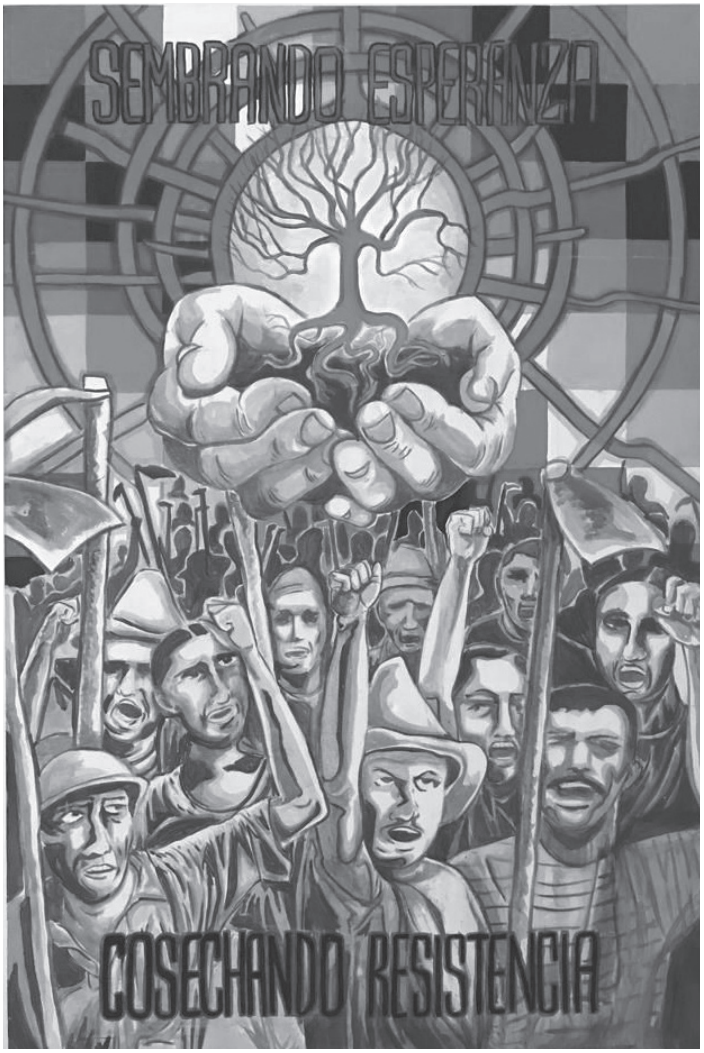

उम्मीद के बीज, विरोध की फ़सल पर पोस्टर
(आभार: पैट्रीशिया बोटेरो–गोमेज़)

पदार्थों को बढ़ावा देना। जो परिवार पहले सुपरमार्केटों से खाद्य पदार्थ खरीदते थे वे अब पटरियों से अपने खाद्य पदार्थ खरीदते हैं। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में मदद कर रहा है, जिसके कारण सामाजिक ताना–बाना भी फिर से स्वस्थ हो रहा है।

इस मुश्किल समय में, किसान परिवारों के लिए अकोरा एक बड़ा सहयोग रहा है। उनका संगठन मज़बूत है और समुदाय अपने जीवन के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की आवश्यकता महसूस करता है। एसोसिएशन ने समुदाय के जीवन की स्थितियों को बेहतर बनाने का प्रयास किया है, और इसके माध्यम से इस विश्वास को ठोस बनाया है कि एकजुटता और सामूहिक कार्य करना उनके काम के प्रमुख पहलू हैं।

संदर्भ:

अलज़ाते, सी. (२०१७)। ला पापेलेरा क्यू देवोरा कोलंबिया। https://colombiaplural.com/carton-devora-colombia-smurfit-kappa/ पर उपलब्ध।

सम्पर्क:

लीना मारसेला मेनेसेस कबरेरा – सुरकोमुन, यूनका वासी फाउंडेशन, यूनिटिएरा मनिज़ेल्स कालडास (marce15120hotmail.com mailto:marce15120hotmail.com>), पैट्रीशिया बोटेरो–गोमेज़ (jantosib@gmail.com mailto:jantosib@gmail.com>)

✧✧

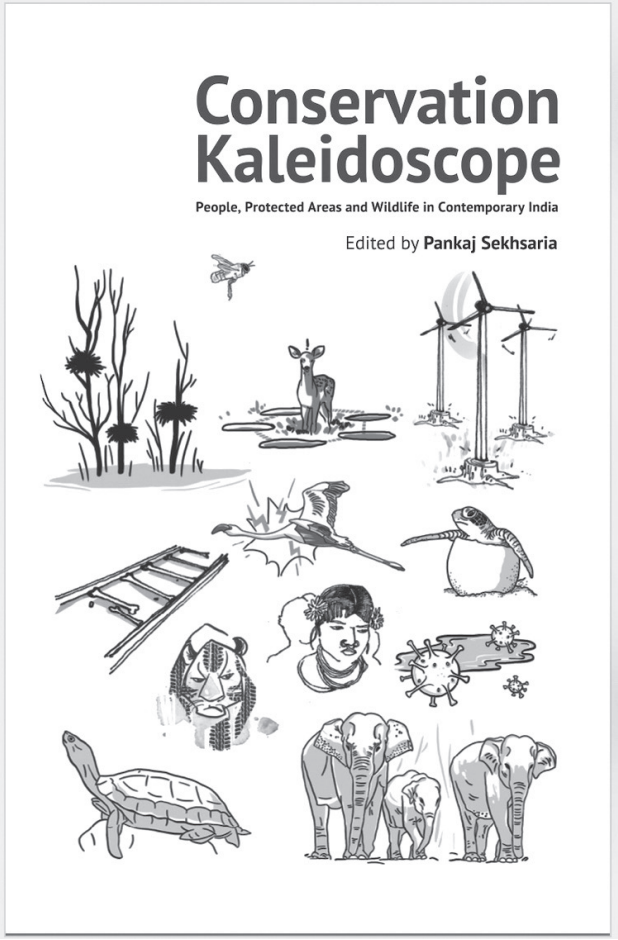

Conservation Kaleidoscope is a collection of over a 100 editorials and accompanying news items that have appeared over the last two decades in the Protected Area Update.

Written by the newsletter's long-time editor, Pankaj Sekhsaria, the individual editorials offer an interesting and often counter-intuitive account of the state of wildlife conservation and protected area management in contemporary India. Organised over 14 broad themes in this collection, the book offers a ringside view of conservation that is as challenging and informative as it is insightful and provocative.

Title: Conservation Kaleidoscope - People, Protected Areas and Wildlife in Contemporary India

Editor: Pankaj Sekhsaria
Publishers: Kalpavriksh, Duleep Mathai Nature Conservation Trust and AuthorsUpFront.
Year of Publication: 2021
ISBN: 978-9-38728-070-0
Size: 6.10 X 9.25 inches | 432 pages
Binding: Paperback
Price: Rs. 650

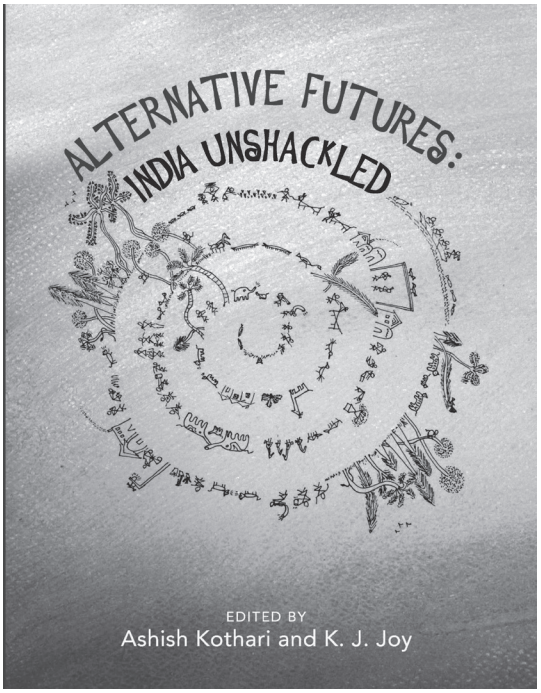

A unique collection of 35 essays on India's future, by a diverse set of authors – activists, researchers, mediapersons, those who have influenced policies and those working at the grassroots. It brings together scenarios of an India that is politically and socially egalitarian, radically democratic, economically sustainable and equitable, and socio-culturally diverse and harmonious.Divided into four sections—Ecological Futures, Political Futures, Economic Futures and Socio-Cultural Futures—the book covers a wide range of issues including environmental governance, biodiversity, democracy and power, law, agriculture, pastoralism, industry, languages, learning and education, knowledge, health and sexuality among others. Most essays include both futuristic scenarios and present initiatives that demonstrate the possibility of such futures.

Since its publication, the book has been received well in critical reviews, as also in various circles where it has been noticed. Some universities in India and abroad have decided to put it into their recommended readings for students of various subjects.

Title: Alternative Futures: India Unshackled
Editor: Ashish Kothari and K.J. Joy
Publisher: AuthorsUpFront
Year of Publication: 2017
ISBN: 978-8193392478
No of pages: 683
Binding: Paperback
Price: Rs. 1000

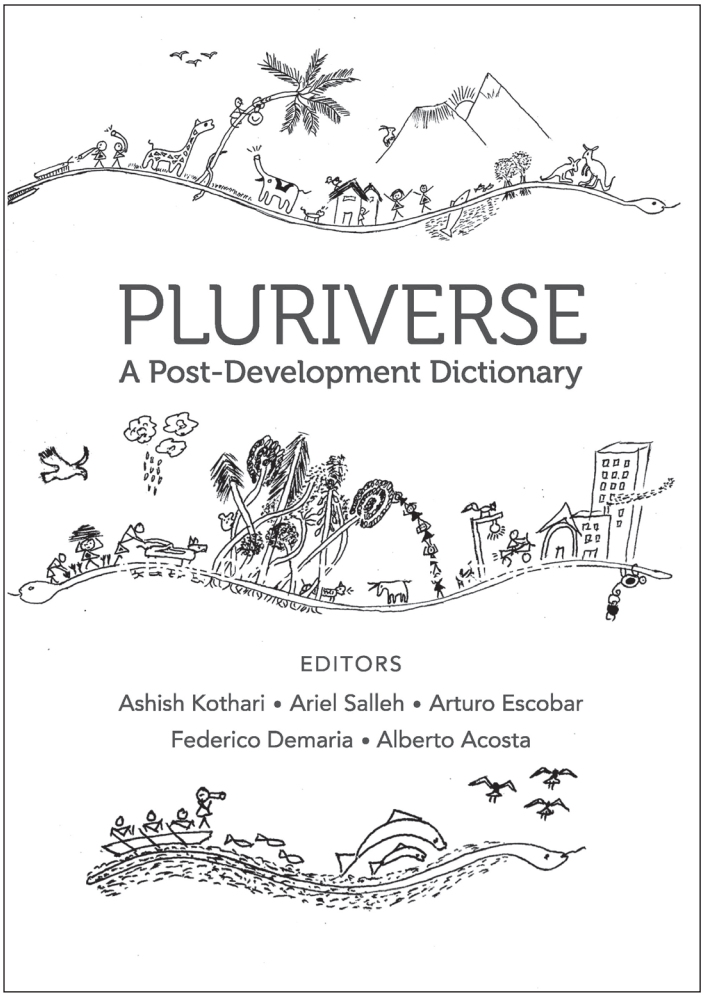

Pluriverse: A Post-Development Dictionary

Over 100 brief, simply written essays on transformative initiatives and alternatives to the currently dominant processes of globalized development, including its structural roots in modernity, capitalism, state domination, racism and masculinist values. The first section contains an essay from each continent critiquing the mainstream model of 'development'. The second section offers critical essays on mainstream solutions that 'greenwash' development. The third (and largest) section presents radically different worldviews and practices from around the world that point to how an ecologically wise and socially just world can be striven for. An introduction by the editors threads all the essays together to offer a synthesis view on the malaise of 'development' and what the pluriverse – a diversity of alternatives, not a singular model – could look like.

Authors/Editors: Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria, and Alberto Acosta
Publishers: Tulika and AuthorsUpFront

Year of Publication: 2019
ISBN: 978-81-937329-8-4
No. of pages: 340
Binding: Paperback
Price: Rs. 850

To order Kalpavriksh publications, please visit : www.kalpavriksh.org/our-store

पाठकों के लिए संदेश:

प्रिय पाठकों, यदि आप समुदाय व संरक्षण की प्रति किसी अलग पते पर प्राप्त करना चाहते है तो कृपया हमें अपना पता milindwani@yahoo.com पर या नीचे लिखे पते पर भेज दें।

कल्पवृक्ष

डॉक्यूमेन्टेशन ऐंड आउटरीच सेन्टर, अपार्टमेंट ५, श्री दत्ता कृपा, ९०८, डेक्कन जिमखाना,

पुणे ४११००४. महाराष्ट्र – भारत

वेबसाइट : www.kalpavriksh.org

समुदाय व संरक्षण : जैव विविधता संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा संस्करण अंक १०, नं. २ सितंबर २०२१ – मार्च २०२२

संकलन एवं संपादन : सुजाता पद्मनाभन

संपादकीय सहयोग : मिलिन्द वाणी

हिंदी अनुवाद : निधि अग्रवाल

कवर फोटो: स्प्रेड एन. ई.

प्रकाशक :
कल्पवृक्ष,
अपार्टमेंट ५, श्री दत्ता कृपा, ९०८,
डेक्कन जिमखाना, पुणे–४११००४.
फोन : ९१–२०–२५६७५४५०,
फैक्स : ९१–२०–२५६५४२३९
ई–मेल : KVoutreach@gmail.com,
वेबसाइट : www.Kalpavriksh.org
आर्थिक सहयोग : मिजेरिओर, आचेव, जर्मनी

निजी वितरण के लिये

प्रकाशित विषयवस्तु (Printed matter)

सेवा में,